04 - आतंकवाद से संघर्ष में पहलगाम आगे

05 - क्या यह गीतोपदेश के पालन का समय है ?

A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 03 मई, 2025

06 - आकर्षक वेदियों पर 740 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, परिजनों को...

07 - जनगणना: मोदी सरकार ने मंडल 3.0 का रिमोट विपक्ष से...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 233, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

प्रसंगवश

जाति जनगणना : राहुल गाँधी का ज़ोर 'तेलंगाना मॉडल' पर क्यों है?

पंकज श्रीवास्तव

राहुल गांधी ने हाल में जाति-जनगणना के लिए 'तेलंगाना मॉडल' को अपनाने की वकालत की है। आखिर इस मॉडल में ऐसा क्या है जो कांग्रेस नेता को प्रभावी और व्यवहारिक लगता है? जानिए इसकी खासियतें और राजनीतिक निहितार्थ।

भारत में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अगली जनगणना के साथ जाति आधारित गणना कराने का ऐलान किया है, जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बदल दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना कराने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या है यह तेलंगाना मॉडल? बिहार मॉडल से यह कैसे अलग है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जाति जनगणना भारत को जातिविहीन समाज की ओर ले जाएगी या जातिगत विभाजन को और गहरा करेगी?

कुछ साल पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को 'पाप' तक करार दिया था। लेकिन 30 अप्रैल 2025 को अचानक सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की, जिसे कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद के बीच एक अप्रत्याशित कदम मान रहे हैं। हालांकि, जनगणना कब होगी, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है, खासकर जब यह प्रक्रिया पहले ही पांच साल देरी से चल रही है।

लंबे समय से जाति जनगणना को सामाजिक न्याय का केंद्रीय मुद्दा बनाने में जुटे राहुल गाँधी ने इस घोषणा पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केवल घोषणा पर्याप्त नहीं है; सरकार को समय-सीमा और तेलंगाना मॉडल को अपनाने की बात स्पष्ट करनी होगी। राहुल गाँधी बीते कुछ सालों से सामाजिक न्याय और संविधान बचाने पर जिस तरह ज़ोर दे रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई, जबकि दावा चार सौ पार का था।

तेलंगाना में 6 नवंबर 2024 को शुरू हुआ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, और जातिगत सर्वे 50 दिनों में 96.9 प्रतिशत घरों तक पहुंचा। इस प्रक्रिया में 94,863 गणनाकार और 9,628 सुपरवाइजर ने 94,261 गणना ब्लॉकों में काम किया। सर्वे में 80 से अधिक प्रश्न पूछे गए, जिनमें आय, शिक्षा, जमीन स्वामित्व, सरकारी नौकरियों, और व्यवसाय में भागीदारी जैसे व्यापक पैरामीटर शामिल थे।

सर्वे से पहले सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवियों से राय ली गई, और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने काम किया। इसकी पारदर्शिता और व्यापकता के कारण राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट बताया।

वहीं, बिहार में 2022 में शुरू हुआ जाति आधारित सर्वे दो चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण (7-21 जनवरी 2023) में घरों की गिनती हुई, और दूसरे चरण (15 अप्रैल-15 मई 2023) में जाति और सामाजिक-आर्थिक डेटा इकट्ठा किया गया। 2.64 लाख गणनाकारों ने 2 करोड़ 90 लाख घरों का सर्वे किया, जिसमें 17 अनिवार्य प्रश्न पूछे गए। डेटा संग्रह के लिए बीजगा ऐप का उपयोग हुआ। हालांकि, यह सर्वे मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचे पर आधारित था और इसमें जनता की राय कम शामिल थी, जिसे राहुल ने 'भ्रामक' और 'अफसरशाही' करार दिया।

सर्वे के नतीजों के अनुसार, तेलंगाना में OBC 56.33 प्रतिशत, SC 17.43 प्रतिशत, ST 10.45 प्रतिशत, और अन्य जातियां 15.79 प्रतिशत हैं। इन आंकड़ों के आधार पर उप-जातियों को लाभ देने के लिए नीतियां बनाई गईं। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले से प्रेरित होकर, तेलंगाना ने OBC के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास किया, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।

पिछड़ा वर्ग (EBC) 36 प्रतिशत, SC 20 प्रतिशत, ST 2 प्रतिशत, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 10 प्रतिशत हैं। इन आंकड़ों के आधार पर बिहार ने आरक्षण को 65 प्रतिशत (EWS के 10 प्रतिशत सहित 75 प्रतिशत) तक बढ़ाया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

कई लोग तर्क देते हैं कि जाति जनगणना आधुनिक युग में कबीलाई व्यवस्था की ओर ले जाएगी। लेकिन वैश्विक परिदृश्य कुछ और कहता है।

अमेरिका: हर 10 साल में जनगणना ब्यूरो नस्ल, जातीयता, लिंग, और आयु के डेटा इकट्ठा करता है, जिसका उपयोग अफर्मेटिव एक्शन नीतियों के लिए होता है।

दक्षिण अफ्रीका: रंगभेद के बाद ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नीति के तहत नस्ल आधारित डेटा का उपयोग अश्वेतों को प्राथमिकता देने के लिए होता है।

ब्राजील: नस्ल आधारित जनगणना के आधार पर विश्वविद्यालयों में कोटा सिस्टम लागू है।

यूरोपीय संघ: कई देश प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी नीतियां बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कल्याणकारी राज्य अपने समाज के पिछड़े समूहों की स्थिति जानना चाहता है ताकि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो सके।

भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच-नीच में बांटा है। मध्यकाल में बसवन्ना, कबीर, रैदास, और गुरु नानक जैसे संतों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 19वीं सदी में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। स्वतंत्रता के पहले ही डॉ. आंबेडकर सामाजिक प्रश्नों को पूरी ताकत से उठा रहे थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस को भविष्य का खाका खींचने में मदद की। डॉ. आंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और यह तय किया गया कि आज़ाद भारत में अस्पृश्यता अपराध होगी और दलितों-आदिवासियों को पहले दिन से आरक्षण मिलेगा। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत OBC आरक्षण ने सामाजिक न्याय को और मजबूती दी।

राहुल गांधी अब इस क्रांति को और तेज करना चाहते हैं। उनकी मांग है- 'जितनी आबादी, उतना हक', निजी शिक्षा और निजी क्षेत्र में आरक्षण। आलोचकों का कहना है कि इससे जाति प्रथा मजबूत होगी, लेकिन समर्थक मानते हैं कि यह ऊंची जातियों की श्रेष्ठता को तोड़ेगा और संसाधनों का बंटवारा समान होगा। अंतर्जातीय विवाह और महिला सशक्तीकरण जैसे कदम जाति व्यवस्था को कमजोर करेंगे।

जाति जनगणना केवल आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है; यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक कदम है। अगर यह तेलंगाना मॉडल की तरह पारदर्शी और व्यापक होगी, तो यह नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही, यह समाज को जातिविहीन बनाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा, जैसा कि डॉ. आंबेडकर और महात्मा गांधी ने भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर सुझाया था। यह एक ऐसी यात्रा है, जो भारत को न केवल सामाजिक न्याय की ओर ले जाएगी, बल्कि एक नई आर्थिक व्यवस्था की खोज को भी मजबूर करेगी, जो सभी की जरूरतों को पूरा कर सके। यह न भूलिए कि आरक्षण ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, शासन-प्रशासन में भागीदारी का उपक्रम है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

आज का इवेंट

कई लोगों की कर देगा नींद हराम

केरल से पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, पास में बैठे थे थरूर

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन का एक ''स्तंभ'' बताया और उन्हें एवं मंच पर मौजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कहा कि उद्घाटन समारोह कई लोगों की ''रातों की नींद हराम'' कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा,मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप इंडी गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ हैं, शशि थरूर जी भी यहीं बैठे हैं। आज का यह कार्यक्रम बहुतों की नींद हराम देगा। हालांकि, उनके भाषण का अनुवाद करने वाले व्यक्ति ने इसका ठीक से अनुवाद नहीं किया, जिस पर प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि ''संदेश उन तक पहुंच गया है, जिन तक यह संदेश पहुंचाना था''। इस बंदरगाह परियोजना को अडानी समूह द्वारा विकसित किया गया है, जो अक्सर विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहता है। यही वजह रही कि मंच पर थरूर और विजयन की उपस्थिति और प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बन गई।

10 वर्षों में हमारे बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई

देश में विकास का ब्योरा देते हुए मोदी ने कहा कि जहाजों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है और पिछले 10 वर्षों में हमारे बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है, उनकी दक्षता में सुधार हुआ है और वहां 'टर्नअराउंड' समय में 30 प्रतिशत की कमी आई है। 'टर्नअराउंड' समय किसी बंदरगाह पर एक जहाज के पहुंचने से लेकर उसके प्रस्थान तक का कुल समय होता है। मोदी ने कहा कि इस बंदरगाह का निर्माण 8,800 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और निकट भविष्य में इसके 'ट्रांसशिपमेंट हब' (माल ढुलाई एवं लदान केंद्र) की क्षमता तीन गुना हो जाएगी। उन्होंने कहा, ''इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी

उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को यह जानकर निराशा होगी कि अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम ने केरल में इतना बड़ा बंदरगाह बनाया है, जबकि वे पश्चिम भारतीय राज्य से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन द्वारा कॉरपोरेट इकाई अदाणी समूह को वामपंथी सरकार का साझेदार बताना देश में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने गुलामी से पहले के दौर का भी जिक्र किया और कहा कि भारत हजारों सालों तक समृद्धि के साथ फलता-फूलता रहा। उन्होंने कहा, ''एक समय ऐसा था जब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। उस समय भारत को अन्य देशों से अलग करने वाली बात इसकी प्रभावशाली समुद्री क्षमताएं और इसके बंदरगाह शहरों में संपन्न आर्थिक गतिविधियां थीं।

सुप्रभात

तेरी बातों में आ कर रख दिया है,
ले, हमने दिल जला कर रख दिया है।
जहाँ पर बे-कली थी, उस जगह पर
किसी ने सब्र ला कर रख दिया है।
वो तेरा हिज्र है कि जिसने कमरा
किताबों से सजा कर रख दिया है।
तेरी तस्वीर लगनी थी जहाँ पर,
वहाँ शीशा लगा कर रख दिया है।
बहुत खुश हूँ कि जाने किस जगह पर
तेरे ग़म को छुपा कर रख दिया है।

- अनवर क़ुरैशी

जनगणना-2011 की गलती दोहराना नहीं चाहती सरकार

पिछली बार 46 लाख जातियां गिनी थीं,इस बार अलग है प्लान

पहले जातियों की सूची बनेगी,उसी आधार पर होगा जाति चयन

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में अब तक कुल 8 बार जातीय जनगणना हुई है। 1872 से 1931 के बीच 7 बार ब्रिटिशकाल में और एक बार 2011 में आजाद भारत में। हालांकि, 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। जातीय जनगणना की घोषणा के साथ ही सरकार ने इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनानी भी शुरू कर दी है। वर्ष 2011 की जातीय जनगणना में जो गलती हुई थी, केंद्र सरकार इस बार उसे दोहराना नहीं चाहती। तब सरकार ने जातियों की पहले से कोई सूची नहीं बनाई थी, जिसने अपनी जो भी जाति बताई, उसे ही दर्ज करते गए। नतीजा ये हुआ कि 46 लाख से भी ज्यादा जातियां

दर्ज हो गईं। इस बार सरकार 1931 में गिनी गई करीब 4 हजार जातियों/उपजातियों को आधार बनाकर पहले से ही सूची तैयार करेगी। एससी/एसटी/ओबीसी आयोग की मदद से सूची तैयार की जाएगी। फिर कर्मचारी यही सूची लेकर घर-घर जाएंगे और इसमें दर्ज जातियों में से ही जाति चुनेंगे।

जनगणना के लिए महापंजीयक का बजट भी बढ़ेगा- जनगणना महापंजीयक का बजट भी बढ़ाने की संभावना है, जो इस साल घटकर 574.80 करोड़ रु. रह गया था। बता दें 2011 की सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना पर 4,389 करोड़ रु. खर्च हुए थे। केंद्र ने 2019 में जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रु. मंजूर किए थे। इसके अलावा 3,941 करोड़ रु. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने के लिए रखे गए। फिर 2020-21 के बजट में जनगणना, सर्वे और सांख्यिकी जुटाने के लिए 4,278 करोड़ रु का प्रावधान किया गया।

पहलगाम हमले के बाद खौफ में पाकिस्तान

पीओके में लोगों को दिया राशन इकट्ठा करने का आदेश

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय प्रशासन ने सीमा के पास रहने वाले लोगों को दो महीने के लिए खाद्यान्न सामग्री का भंडार करने का आह्वान किया है। स्थानीय प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तानी सेना लगातार पिछले आठ दिनों से सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने शुक्रवार को स्थानीय विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नियंत्रण रेखा के पास स्थित 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को दो महीने का खाद्यान्न भंडार रखने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री एकात्म धाम ओंकारेश्वर में शंकर प्रकटोत्सव में हुए सम्मिलित

चरणबद्ध रूप से होगा एकात्मधाम को पूर्ण करने का कार्य : सीएम डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा व आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली को राज्य सरकार एकात्म धाम के रूप में विकसित कर रही है, जो चरणबद्ध रूप से पूर्ण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में अनेक महान कार्य किए। गुरु शंकराचार्य की चेतना शास्त्र परंपरा से हमारा परिचय कराती है। भारत को शक्ति संपन्न बनने के लिए ज्ञान, आध्यात्म, शास्त्र एवं शस्त्र सभी विधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे संतों एवं संन्यासियों ने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा का अद्भुत समन्वय किया है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत को केवल शास्त्रों से नहीं, शस्त्रों की परंपरा से भी सशक्त बनाना होगा। इस मौके पर 500 शंकरदूतों को दीक्षा दी गई। अद्वैत लोक निर्माण और धार्मिक नगरों में शराब मुक्ति जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार की नीतियां गिनाईं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी की शुरुआत की है। शराब की दुकानें बंद कर दूध की दुकाने खोली जा रही है। दुग्ध उत्पादन को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सांस्कृतिक पर्वों एवं त्यौहारों को समाज के साथ समारोहपूर्वक मनाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति से जुड़ाव और सामाजिक आयोजनों के लिये सम्पूर्ण प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और संस्कृति विभाग द्वारा एकात्म धाम, ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव पर पंच दिवसीय 'एकात्म पर्व' के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि ने की। इस अवसर पर महर्षि संदीपनी वेद विद्या पीठ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने एकात्म धाम की यज्ञशाला की पवित्र यज्ञ-वेदी में आहुति दी। उन्होंने यज्ञ की परिक्रमा कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साधु-संतों के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संतों का स्वागत कर 'एकात्म धाम : एकात्मता की यात्रा' पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही अद्वैत वेदांत के आचार्य स्वामी विदितात्मानंद सरस्वती एवं प्रो. व्ही कुटुम्ब शास्त्री का अलंकरण किया गया। कार्यक्रम में अद्वैत जागरण युवा शिविर पर केंद्रित फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एकात्म धाम में संतों के वचनों का श्रवण कर ऐसा लगा जैसे गागर में सागर भर दिया हो। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष के लघु जीवन काल में इतने महान कार्य किये जो कल्पना से परे हैं।

यूपी में एक्सप्रेस-वे पर 15 एयरक्राफ्ट की टच एंड गो प्रैक्टिस, दंग हुए लोग

राफेल-जगुआर, मिराज ने दिखाई ताकत;पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल भी

शाहजहांपुर (एजेंसी)। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस-वे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी-तूफान के बीच 'टच एंड गो' किया। सबसे पहले सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेस-वे पर 'टच एंड गो' किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। सिर्फ एएन-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेस-वे पर लैंडिंग की। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान को 180 डिग्री घुमाकर उसका रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। बीते रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार 3.5 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी का निरीक्षण किया था। यह देश की पहली ऐसी पट्टी होगी,जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात में उतर सकेंगे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 22 °c

न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 03 मई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

न कोई एयरक्राफ्ट कैरियर न ही ताकतवर डिस्ट्रॉयर

पनडुब्बियां भी आधी, भारत के आगे पिद्दी है पाक नेवी

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बीच बुधवार को पाकिस्तान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के इस बयान के बीच एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत से जंग का मुकाबला कर सकता है। समुंदर में पाक की सेना भारत के सामने पिद्दी नजर आ रही है। अगर जंग हुई तो भारतीय नौसेना की ताकत पाकिस्तान से दोगुनी है। ग्लोबल फायरपावर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इतना ही नहीं नौसेना के अन्य पहलुओं पर पाकिस्तान की तुलना करें तो भारतीय नौसेना के पास कुल 293 लड़ाकू और सहायक जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान की पूरी नौसेना केवल 121 संसाधनों तक सीमित है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं।

आंधी-बारिश से 10 लोगों की मौत

- दिल्ली में 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रहीं डिले

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी-बारिश और बिजली-पेड़ गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4-4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली-एनसीआर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से

200 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 3 को डायवर्ट भी करना पड़ा। 2 को जयपुर और एक अहमदाबाद में लैंड करवाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोज करीब 1,300 उड़ानों की आवाजाही होती है।

प्रज्ञा की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई रुकी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ट्रायल कोर्ट में फैसला आने वाला है

भोपाल (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी है। यह याचिका पीड़ितों में से एक के पिता निसार अहमद ने 2017 में दायर की थी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट ने बताया कि अब एनआईए कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई न करे।

जुरासिक पार्क से लेकर हैरी पॉटर वर्ल्ड का मिलेगा एडवेंचर

यूनिवर्सल स्टूडियो का थीम पार्क भारत लाने का है प्लान, अभी केवल चार देशों में है

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया के सबसे आइकॉनिक एंटरटेनमेंट ब्रांड्स में से एक यूनिवर्सल स्टूडियो अपना एंटरटेनमेंट एंपायर जल्द ही भारत ला सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल थीम पार्क ऑपरेटर भारती रियल एस्टेट के साथ भारत में अपना पहला इनडोर एम्यूजमेंट पार्क स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है।

यूनिवर्सल स्टूडियो ब्लॉकबस्टर फिल्मों, थ्रिलिंग राइड और इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। अमेरिका, जापान, सिंगापुर और चीन में स्थित इस ब्रांड के कारण हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं।

यूनिवर्सल स्टूडियो के भारत आने से न केवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। दिल्ली एयरपोर्ट के पास भारती के अपकमिंग 3 मिलियन वर्ग फीट मॉल के भीतर स्थित होने की उम्मीद है। भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और सिनेमा के प्रति प्रेम इसे यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए एक

आइडियल मार्केट बनाते हैं।

भारती रियल एस्टेट के सीईओ एसके सयाल ने पुष्टि की कि 3 लाख वर्ग फीट के टोटल डेवलपमेंट में से लगभग 10 फीसदी स्पेस, एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पार्क के लिए रखा गया है। हालांकि सयाल ने सीधे तौर पर यूनिवर्सल स्टूडियो का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पोटेंशियल इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ चर्चा चल रही है।

यूनिवर्सल स्टूडियो इंडिया बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों, रामायण जैसे पौराणिक महाकाव्यों और क्षेत्रीय सिनेमा से इंस्पायर्ड अट्रैक्शन पेश कर सकता है। मॉडर्न यूनिवर्सल पार्कों में वर्चुअल रियलिटी (वीआर), ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) और मोशन-सिम्युलेटर राइड्स शामिल हैं। इसे भी पेश किया जाय सकता है। हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में बटरबीयर से लेकर लोकप्रिय फिल्मों पर बेस्ड थीम रेस्तरां यहां हो सकते हैं। अभी तक, बातचीत चल रही है, और अगर इसे अंतिम रूप दिया जाता है, तो निर्माण में 5-7 साल लग सकते हैं। पार्क 2030 तक या उसके बाद खुल सकता है।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस जारी

- राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा नोटिस 8 मई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इन सभी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। कोर्ट ने अगली तारीख 8 मई, 2025 तय की है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को चार्जशीट पर सुनवाई का पूरा हक है।

कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए ये जरूरी है कि हर आरोपी को सुना जाए। इसलिए नोटिस जारी करना जरूरी था। कोर्ट चाहता है कि सभी आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मामले की सुनवाई सही तरीके से हो। इससे पहले अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को अभी नोटिस जारी करने से मना कर दिया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया था। ईडी का कहना है कि नए नियमों के अनुसार, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि नोटिस जारी करना जरूरी है। ईडी का कहना है कि कानून बदल गया है। नए कानून के हिसाब से, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले, नोटिस जारी किया जाए। जज ने 25 अप्रैल को सुनवाई में कहा था कि पहले अदालत को यह देखना होगा कि नोटिस जारी करना जरूरी है या नहीं।

लैंडिंग के दौरान बाल-बाल बचे बिहार के मुख्यमंत्री

- हेलीकॉप्टर में थे नीतिश कुमार और उड़ने लगा टीन शेड

पटना (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार शुक्रवार को बाल-बाल बचे। नालंदा जिले के राजगीर में उनके हेलिकॉप्टर की लैंडिंग के समय टीन शेड (करकट) उड़ने लगा। वीडियो देखने से लग रहा है कि दो-दो टीन के शेड उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर से महज कुछ दूरी पर ये सब हो रहा था। ये हादसा तब हुआ जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर से राजगीर पहुंचे थे। गनीमत रही कि टीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर से दूर गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद सीएम की सुरक्षा में लगे कर्मचारी भी सहम गए। हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई, लेकिन इस घटना ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर कर दी। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतिश कुमार शुक्रवार सुबह पटना से हेलीकॉप्टर से राजगीर के लिए रवाना हुए थे। राजगीर में जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, तो उसके पास रखा टीन शेड हवा में उड़ गया। यह देखकर वहां मौजूद अधिकारी घबरा गए। हेलीकॉप्टर जब नीचे उतरता है तो हवा की गति बहुत तेज होती है।

धर्म ही बदल लिया तो फिर कैसे रह गए दलित

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया एससी-एसटी एक्ट का केस

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसका एससी का दर्जा भी खत्म हो जाता है। ऐसे में वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।

हाईकोर्ट के एकल बेंच पर जस्टिस हरिनाथ ने गुंटूर जिले के रहने वाले अक्कला रामी नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बयान दिया। अक्कला पर आरोप था कि उसने हिंदू से ईसाई बने एक चिंतादा नामक शख्स को जातिसूचक गालियां दी हैं। अक्कला के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि चिंतादा ने दावा किया है कि वह एक स्थानीय चर्च में पादरी के तौर पर काम कर रहा है। उसने दशक से भी ज्यादा समय पहले अपनी मर्जी से अपने धर्म को बदला था। अब जब ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को

मान्यता नहीं देता है, तो फिर एससी-एसटी एक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जस्टिस हरिनाथ ने कहा कि जब चिंतादा खुद ही कह रहा है कि वह पिछले 10 सालों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, तो पुलिस को आरोपी के ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत केस नहीं करना चाहिए था। जस्टिस हरिनाथ ने अक्काला के वकील के तर्क को मानते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट उन समुदायों से जुड़े व्यक्तियों की रक्षा के लिए हैं न कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के लिए नहीं। स हरिनाथ ने आरोपी पर से लगे केस को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि संविधान में भी अनुसूचित जाति 1950 के मुताबिक केवल भारत में पैदा हुए धर्मों (हिंदू, सिख, बौद्धों) के अनुसूचित जाति समुदायों को ही मान्यता प्राप्त है। अगर कोई इन धर्मों में है, तो उसे अनुसूचित जाति में माना जाएगा। वहीं अगर कोई मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसका यह दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया था कि ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह इस धर्म को अपनाते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें छुआ-छूत का सामना न करना पड़े।

बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश रच रही आईएसआई

नॉर्थ-ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की हो रही है कोशिश

एजेंटों के साथ पाक हाई कमिश्नर ने कर ली 2 सीक्रेट बैठकें

नई दिल्ली, ढाका (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। ढाका के पाक उच्चायोग में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारुफ कट्टरपंथी जमात, हिफाजत और खिलाफत मजलिस के साथ दो बार सीक्रेट बैठकें कर चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के मंसूबे भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में अलगाववादियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने और घुसपैठ के लिए उकसाने के हैं। उधर, पाकिस्तान ने एलओसी पर सातवें दिन भी सीजफायर तोड़कर फायरिंग की। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि कुपवाड़ा, अखनूर और उरी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने अटारी-वाघा बॉर्डर गुरुवार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पिछले 7 दिन के दौरान भारत से 911 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया है।

बंगाल सरकार के नए मंदिर 'जगन्नाथ धाम' को लेकर विवाद

यह नाम देना हिन्दू मान्यताओं-परंपराओं के खिलाफ

भुवनेश्वर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में विरोध शुरू हो गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों और शोधकर्ता मंदिर का नाम 'जगन्नाथ धाम' रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर को 'जगन्नाथ धाम' नाम दिया। ओडिशा के लोगों ने मंदिर बनाने का समर्थन किया, लेकिन नाम पर एतराज जताया। उनका कहना है कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, अन्य मंदिर को यह नाम देना हिन्दू मान्यताओं-परंपराओं के खिलाफ है।

अटारी बॉर्डर पर फंसे पाक नागरिकों के लिए खुला गेट

- 1008 पाक नागरिक लौटे, 1575 भारतीय भी वापस आए, कई मरीज इलाज अधूरा छोड़ लौटे

अमृतसर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुए तनाव में पाकिस्तान ने एक बार फिर गेट को अपने नागरिकों के लिए खोल दिया है। बीते दिन, गुरुवार, पाकिस्तान ने गेटों को नहीं खोला था, जिसके चलते पाकिस्तानी नागरिक, जो पाक जाने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंचे थे, वे फंस गए थे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहना है- पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा अचानक रद्द किए जाने के कारण कई मरीज इलाज पूरा किए बिना गंभीर हालत में वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौटे हैं। इस निर्णय के कारण कई परिवार जबरन बिछड़ गए, जिनमें बच्चे भी अपने माता-पिता से अलग हो गए। हालांकि वाघा सीमा से लौटने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ पाकिस्तानी नागरिक अभी भी अटारी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। अगर भारतीय प्रशासन अनुमति देता है, तो हम अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।

कास्ट सेंसस के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा बिहार चुनाव

- मुस्लिमों में भी जाति को लेकर अहम माना जा रहा यह फैसला ● आजादी के बाद पहली बार भारत में हो रही जातीय जनगणना

पटना (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। संघ, सहयोगी दल, विपक्ष और बिहार विधान सभा चुनाव 2025 को अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मुद्दों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक और बात कही जा रही है कि क्या ये धर्म के नाम पर एकजुट हुए मुस्लिमों को बांटने का प्रयास है। इसका असली इम्तिहान बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सरकार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरने के लिए यह कदम उठाया है। वे कहते हैं कि जातीय जनगणना से इन नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। एक और चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार धर्म के आधार पर एकजुट

हुए मुस्लिमों को बांटना चाहती है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना से मुस्लिम समुदाय अलग-अलग जातियों में बंट जाएगा। **सियासी नफा-नुकसान की तराजू पर कास्ट सेंसस-** वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद जो देश भर में मुस्लिमों ने जो एकता दिखाई वो भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया। सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक सलाहकार इस जनगणना के जरिए इस्लाम को भी जातियों में बांट कर बिहार विधान सभा चुनाव का परिणाम देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव निराला यादव कहते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है, वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में लिया गया है। लेकिन, जब ये दबाव बनाया जा रहा था, तब ये फैसला न लेकर अब चुनाव के मौके पर निर्णय लिया गया।

मुस्लिम में जातीय-व्यवस्था से इनकार नहीं: दानिश

बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का मानना है कि जो लोग भी मुस्लिमों में जातीय-व्यवस्था को नकारते हैं, वे लोग मुस्लिम समाज को पीछे रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज विकास के पायदान पर आगे बढ़े। मुस्लिम समाज में जातीय व्यवस्था है। मैंने कई भारतीय उलेमाओं की रचनाएं भी पढ़ी है, जिन्हें उनके कई अनुयायी महान बुद्धिजीवी मानते हैं। जैसे- मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी और मौलवी अशरफ अली फारुकी थानवी। जातिगत श्रेष्ठता की धारणा का समर्थन किया।

जनजातीय छात्रों के लिए 51 छात्रावासों की स्वीकृतिः मंत्री डॉ. विजय शाह

भोपाल(नप्र)। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) में जनजाति वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए 51 छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि छात्रों को मात्र शिक्षण संस्थान ही नहीं उनके लिए छात्रावास की उपलब्धता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अभियान में ऐसे 1296 गाँव चिन्हित किए गए हैं जहां 5 कि. मी. में कोई भी माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ऐसे गाँवों में छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

117.30 करोड़ के प्रस्ताव

जनजातीय छात्रावासों के लिए विद्यालय रहित चिन्हित ग्रामों में केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक 51 छात्रावासों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें 22 छात्रावासों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है। शेष 29 छात्रावासों के लिए डीपीआर तैयार है। छात्रावास गति शक्ति पोर्टल के अनुसार इसके अलावा 38 और छात्रावासों की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा है। इस पर प्रति यूनिट 2.3 करोड़ की दर से 117.30 करोड़ की लागत से कार्य योजना तैयार की गई है।

24 जिले, 1296 गाँव

मंत्री डॉ. विजय शाह ने बताया कि इस अभियान में जनजाति छात्रावासों के लिए प्रदेश के 24 जिलों के 1296 गाँव चिन्हित किए गए हैं। छात्रावासों के निर्माण के लिए तीन चरणों में स्वीकृति प्रस्ताव चलन में हैं। समग्र शिक्षा में छात्रावासों के लिए ऐसे गाँवों को चिन्हित किया गया है जहाँ 5 किमी के दायरे में माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। इस श्रेणी में शिवपुरी जिले में 192 गाँव चिन्हित किए गए हैं। शिवपुरी के लिए 9 छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया चलन में है। इनमें 5 छात्रावासों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है शेष 4 छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस क्रम में 129 गाँवों के साथ विदिशा दूसरे नंबर पर है, जहां 6 छात्रावासों के निर्माण के लिए तृतीय चरण में प्रस्ताव भेजे गए हैं। तीसरे स्थान पर 125 स्थानों के साथ शहडोल है जहां 6 छात्रावासों कि स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही नरसिंपुर में न्यूनतम 5 गांव चिन्हित किए गए हैं। न्यूनतम क्रम में इसके बाद 7 स्थानों के साथ मुरैना जिला है जहाँ चिन्हित छात्रावासों की संख्या 4 है जिनके प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।

जातीय जनगणना, वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का रास्ता : प्रदीप अहिरवार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को पार्टी ने ओबीसी में एससी-एसटी जातियों के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इस दौरान जातिगत जनगणना कराने की घोषणा को पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत बताया। मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि जातिगत जनगणना केवल समय की मांग नहीं है, बल्कि यह देश के वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने का रास्ता है। राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, जिसका भाजपा ने कई बार मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज यह एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है।

जातिगत आंकड़े के बिना सरकारी योजनाओं को सफल नहीं माना जाएगा

अहिरवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि जातिगत आंकड़े को सामने लाए बिना किसी भी सरकारी योजना को सफल नहीं माना जा सकता।

राज्यपाल मंगु भाई पटेल से म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने शुक्रवार को राजभवन में सौजन्य भेंट की।

वेव्स में मध्यप्रदेश पवेलियन में 150कलाकारों ने 10 नृत्य किए

सांस्कृतिक, पर्यटन, इतिहास-कलां का प्रदर्शन ; रैम्प वॉक भी किया

भोपाल (नप्र)। मुंबई में हुए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट-2025 (वेव्स) में 'अतुलनीय मध्यप्रदेश' पवेलियन में शुक्रवार को सांस्कृतिक, पर्यटन, इतिहास, कलां और परंपराओं का अनूठा प्रदर्शन हुआ। डेढ़ सौ से अधिक कलाकारों ने 10 नृत्य किए। वहीं, रैम्प वॉक भी किया।

नृत्य नाटिका के जरिए मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, समृद्ध पर्यटन, इतिहास, कला और परंपराओं को दर्शाया गया। इसमें हृदय प्रदेश के सांस्कृतिक रंग, सघन वन, ऐतिहासिक स्थल, टेक्सटाइल, परंपराएं आदि की अनुभूति और आनंद दर्शकों ने लिया। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में इस नृत्य नाटिका में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी के साथ ही मध्यप्रदेश के बधाई, बरेदी, मटकी, गोंड, जैसे लोकनृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा नृत्य नाटिका में मुमताज खान के निर्देशन में मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल जैसे महेश्वरी, चंदेरी, बाग के वैभव को दर्शाता एक विशेष वॉक भी हुआ।

प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का हुआ संचार-अमृतस्य मध्यप्रदेश एक मनमोहक समवेत नृत्य-नाट्य प्रस्तुति है, जो दर्शकों को भारत के हृदय-मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ती है। यह प्रदर्शन केवल नृत्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हमें हजारों वर्षों पुराने इतिहास, भक्ति, प्रेम, प्रकृति और कला की लय में ले जाती है।

जल गंगा संवर्धन अभियान

सामूहिक श्रमदान से जल स्रोतों की हो रही है सफाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में 30 जून तक चलने वाला जल गंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी के साथ प्रदेश भर में उत्साह के साथ चल रहा है। अभियान में प्रत्येक जिले में जल स्रोतों को चिन्हित किया गया है और उनके संरक्षण व साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मालदेव तालाब पर किया गया श्रमदान

छिंदवाड़ा जिले में जन अभियान परिषद ने विकासखंड परासिया में जल गंगा संवर्धन अभियान में मानका देही खुर्द में मालदेव में तालाब गहरीकरण में श्रमदान कर ट्राली से मिट्टी निकाली। कार्यक्रम में जनपद पंचायत सदस्य श्री कुबेर सिंह सूर्यवंशी, ग्राम के उपसरपंच श्री सिरसाम सहित समाजसेवियों ने नागरिकों के साथ श्रमदान किया। श्रमदान के बाद जल संवाद किया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर रोजगार गारंटी के मजदूरों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

संवाद में जल के महत्व को बताया गया। जन सामान्य को जानकारी दी गई कि अच्छे भविष्य के लिये जल को बचाना जरूरी है। श्रमदान में मास्टर ऑफ सोशल वर्क के छात्रों ने भी श्रमदान किया।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ और आंट में क्षिप्रा नदी की हुई सफाई

देवास जिले में जल है तो कल है, जल की एक-एक बूंद अमृत के समान है। इन वाक्यों के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नदी, नालों, कुएं, बावड़ियों एवं कुंड की साफ-सफाई की जा रही है। जल स्रोतों के आस-पास से गदंगी और गाद को बाहर निकाला जा रहा है। क्षिप्रा शुद्धिकरण सफाई अभियान अंतर्गत जन अभियान परिषद ब्लॉक देवास, बागली, टोंकखुर्द एवं सोनकच्छ के स्वयंसेवकों द्वारा ग्राम पंचायत बैरागढ़ एवं ग्राम पंचायत आंट में क्षिप्रा नदी की सफाई की गई। नदी की साफ-सफाई एवं गहरीकरण होने से बारिश के दिनों में पानी का अधिक संग्रहण होगा और वॉटर लेवल भी बढ़ेगा। ग्रामीणों को पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा।

देवास जिले में अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों के जनसहयोग से जिले की जनपद पंचायत खातेगांव की ग्राम पंचायत बरछाबुजुर्ग में जनसहयोग से नाले का गहरीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड अंतर्गत बागली विकासखंड के ग्राम पुंजापुरा में वॉटरशेड विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। विधायक बागली श्री मुरली भंवरा ने वॉटरशेड वेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड अंतर्गत ग्राम पुंजापुरा में जल कलश यात्रा, जल शपथ, नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस दौरान विधायक बागली श्री भंवरा ने जीवन में जल के महत्व को समझाया और प्रतिभावान कृषक, स्कूली बच्चों तथा आजीविका समूह की महिलाओं का सम्मान किया।

खकनार विकासखंड की ग्राम पंचायतों में जारी हैं विभिन्न निर्माण कार्य

बुरहानपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान व्यापक स्तर पर संचालित हो रहा है। इसी श्रृंखला में खकनार विकासखंड की ग्राम पंचायत लोखंडिया में भोला भावसिंग के खेत के पास तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत खड़की में भी चेक डेम निर्माण का कार्य जारी है।

हर शहर-हर ग्राम में जल को सहेजने और संरक्षण के हो रहे कार्य

शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद पंचायत गोहपारू के नवीन खेत तालाब का निर्माण कार्य ग्राम लफदा, भूरसी, जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम कंचनपुर में किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों में जन-प्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार और नागरिकों की भागीदारी से जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। जन सामान्य को जल की एक-एक बूंद को सहेजने को संदेश दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में किया गया श्रमदान

गुना जिले में ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में ''जल गंगा संवर्धन अभियान'' में श्रमदान किया गया। श्रमदान में विधायक गुना श्री पन्नालाल शाक्य ने सीता कुंड की सफाई में भाग लिया। बजरंगगढ़ में विशेष अभियान में 108 प्राचीन कुओं का चिन्हांकन किया गया है। बजरंगगढ़ एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर रहा है, जिसकी पहचान किले के अतिरिक्त 108 मंदिर और बावड़ी से होती रही है। ऐसे समस्त प्राचीन कुओं एवं बावड़ियों की सफाई के साथ उनके रिचार्ज संरचनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में समस्त जिला प्रशासन की टीम के साथ जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है।

कलेक्टर ने किया जल संरचनाओं का निरीक्षण

नरसिंहपुर जिले में विभिन्न पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और मरम्मत करने के साथ नवीन जल संरचनाओं के निर्माण किये जा रहे हैं। इसमें अमृत सरोवर, खेत- तालाब, कंटूर ट्रेंच-खंती आदि शामिल हैं। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले एवं सीईओ जिला पंचायत श्री दिलीप कुमार ने चांवरपाठा जनपद पंचायत के ग्राम अंजसरा, खुलरी एवं रमपुरा पहुंचकर अमृत सरोवर व खेत-तालाब निर्माण का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने बताया कि ग्राम अंजसरा में लगभग 28 एकड़ शासकीय भूमि अमृत सरोवर निर्माण के लिए चिन्हित की गई है, जिसमें लगभग 10 एकड़ में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि इस भूमि पर बरसात के समय में पानी लबालब भरा रहता है। अमृत सरोवर बन जाने से वर्षभर पानी की उपलब्धता होगी। रोजगार सहायक एवं सचिव ने बताया कि इस क्षेत्र के किसान प्रगतिशील हैं।

ग्राम पंचायत बमूरिया फूट में ग्रामीणों को जल बचाने की दिलाई गई शपथ

अशोकनगर जिले में जन अभियान परिषद विकासखंड अशोकनगर की चयनित नवांकुर संस्था उन्नति जन कल्याण सेवा समिति बिजौरी के मढखेड़ा सेक्टर-एक में ग्राम पंचायत बमूरिया फूट में ग्रामीणों को जल बचाने की शपथ दिलाई गई और जल बचाव के उपाय बताए गए। ग्रामीणों से कहा गया कि बारिश का पानी गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी वॉटर लेवल बढ़ेगा। गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत अशोकनगर की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के प्रत्येक वार्डों में सार्वजनिक प्याऊं तत्काल चालू कराये जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को दिए गए।

राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड जून में प्रथम चरण की परीक्षा करेगा आयोजित

प्रदेश में ड्रॉप-आउट की संख्या को कम करने के लिये किये जा रहे हैं प्रयास

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड इस वर्ष जून माह में प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये 'रूक जाना नहीं' योजना में कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ 'आ लौट चलें' कक्षा 10वीं, 12वीं, ओपन स्कूल परम्परागत परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं, आईटीआई समकक्ष कक्षा 12वीं, सीबीएसई ऑन डिमांड कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 जून 2025 से 2 पारियों में की जा रही हैं।

प्रथम पारी में समस्त 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा द्वितीय पारी में समस्त 10वीं, 8वीं और 5वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की समय-सारणी मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये ई-मेल mpsos2022@gmail.com या मोबाईल ऐप- mpsoseb और फोन नम्बर- 0755-2552106 से भी प्राप्त की जा सकती है।

रूक जाना नहीं योजना

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल से अनुतीर्ण हुए विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण वर्ष खराब नहीं हो, इस उद्देश्य से राज्य शासन की अनुमति से रूक जाना नहीं योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल में नियमित और स्वाध्यायी (प्रायवेट) रूप से शामिल अनुतीर्ण विद्यार्थियों को उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें वे परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पुनः मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस योजना का लाभ लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण करके उच्च अध्ययन के लिये अन्य संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

आ लौट चलें योजना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदान किये गये प्रदेश के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को शिक्षा की मूल धारा में वापस जोड़ने के लिये विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शामिल करने के लिये ऑनलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इनका पाठ्यक्रम व ब्लू प्रिंट वही होता है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश में प्रचलित है, जिससे इन विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या कम करके सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिये मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आ लौट चलें योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 14 से 18 वर्ष के ऐसे विद्यार्थी, जो कि स्कूलों से विभिन्न कारणों से ड्रॉप आउट हो गये हैं, उन्हें ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा में शामिल कराकर मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्टेट हैंगर पर लाड़ली लक्ष्मी स्थापना दिवस पर 'एक पेड़ लाड़ली लक्ष्मी के नाम अभियान' अंतर्गत 25 लाड़ली लक्ष्मियों के साथ पौध-रोपण किया।

ऑपरेशन के बाद युवती की मौत

जिंदल अस्पताल में पैर में गठान की हुई सर्जरी, अस्पताल पर दवा के ओवर डोज का आरोप

भोपाल (नप्र)। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र स्थित जिंदल अस्पताल में घुटने की सर्जरी के लिए भर्ती कराई गई 24 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवती की तबीयत बिगड़ने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने समय पर ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते उसकी जान चली गई। परिवार ने दवा का ओवर डोज देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक मृतका शालू यादव (24) निवासी विकास नगर कॉलोनी, बैरसिया रोड को एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक, गुरुवार को सुबह 11 बजे उसे भर्ती किया गया और शाम 5 बजे ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया था।

शालू के भाई नीतेश यादव ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बहन ने पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसे उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को बताया। उनका दावा है कि रात 1 बजे उसे एक इंजेक्शन दिया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। रात 3:30 बजे जब मां ने जाकर देखा तो वह अचेत थी। हमने फिर से डॉक्टरों को बताया, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे स्पष्ट जानकारी

परिजन का आरोप है कि डॉक्टर्स ने सुबह तक उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। सुबह 6 बजे उन्हें बताया गया कि शालू की मौत हो चुकी है। परिजनों का यह भी कहना है कि डॉक्टर्स ने दो घंटे तक सीपीआप देने की बात कही, लेकिन किसी तरह की गंभीर कोशिश उन्हें नजर नहीं आई। शुक्रवार को शालू का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि पीएम रिपोर्ट आने व जांच के बाद ही कुछ कह पाना ठीक हो। वहीं जिंदल अस्पताल प्रबंधन से जुड़े आशीष अग्निहोत्री ने व्यस्तता का हवाला देते हुए इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने कहा कि- मामले की सूचना मिली है, इस घटना से संबंधित जानकारी ली जा रही है, जांच में जो भी सामने आएगा उसके तहत आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

भोपाल में बिना मान्यता चल रहा स्कूल बेटे की टीसी मांगने पर हुआ खुलासा

चुप रहने स्कूल ने ऑफर किए 15000

भोपाल (नप्र)। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना मान्यता के स्कूल संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। अयोध्या नगर स्थित अरेंडी रोड पर आरपीएच गुरुकुल नामक स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जबकि इसके पास वैध मान्यता नहीं है। स्कूल के गेट पर नर्सरी से कक्षा 4 तक के 'एडमिशन ओपन' का बैनर लगा हुआ है और वर्तमान में लगभग 10 बच्चे यहां पढ़ रहे हैं।

इनमें दिव्यांशु लोधी नाम का एक छात्र कक्षा 2री में पढ़ रहा है। उसके पिता शेषराम लोधी ने बेटे का किसी और स्कूल में प्रवेश कराने के लिए आरपीएच स्कूल से टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) मांगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने बहाने बनाकर टीसी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान शेषराम को पता चला कि स्कूल के पास तो मान्यता ही नहीं है।

चुप रहने के लिए 15 हजार रुपए का ऑफर- शेषराम लोधी ने बताया कि वे एक साल पहले गार्ड की नौकरी मिलने पर परिवार सहित भोपाल आए थे। बच्चों की पढ़ाई के लिए घर के पास मौजूद आरपीएच स्कूल में छोटे बेटे मधुराज का केजी-1 और बड़े बेटे दिव्यांशु का कक्षा 2 में एडमिशन कराया था। जब उन्होंने इस साल टीसी मांगी तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। शेषराम का आरोप है कि स्कूल संचालक और प्रिंसिपल चुप रहने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। कभी 15 हजार रुपए देने की पेशकश की जा रही है, तो कभी झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही है।

स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग से की शिकायत- शेषराम ने स्कूल संचालक और प्रिंसिपल के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और चैटिंग के स्क्रीनशॉट इकट्ठा किए हैं। इसमें स्पष्ट है कि दिव्यांशु को कक्षा 2 में प्रवेश दिया गया था। अब जब मान्यता नहीं होने की बात सामने आई तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने तक उन्हें मान्यता मिल जाएगी, तब तक बच्चा वहीं पढ़ता रहे।

स्कूल का दावा - सिर्फ केजी तक हैं कक्षाएं- स्कूल की प्रिंसिपल रागिनी भारद्वाज ने दावा किया कि स्कूल में केवल केजी-1 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शेषराम लोधी को स्कूल की स्थिति पहले से पता थी और उनके बड़े बेटे को केवल कोचिंग दी गई थी। साथ ही, मान्यता के लिए आवेदन किया गया है।

लव जिहाद को कुचलना राजनीतिक नहीं दिलों का मुद्दा

विधायक रामेश्वर बोले, ऐसा करने वालों को मारा भी जाएगा, कुचला भी जाएगा

भोपाल (नप्र)। राजधानी की हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम धर्म में हिन्दू बेटियों को लव जिहाद में फंसा कर धर्म परिवर्तन कराने पर सवाब मिलता है। यह इस धर्म के लोगों ने स्वीकार किया है। तो अब उन्हें कुचला भी जाएगा और मारा भी जाएगा। अब ऐसा करने वालों को जन्नत भी नसीब होगी। शर्मा ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह राजनीतिक दलों का नहीं दिलों का मुद्दा बन गया है। जिसके विरोध में सम्पूर्ण हिन्दू समाज सड़कों पर है।

मीडिया को दिए बयान में विधायक शर्मा ने कहा है कि हर हिन्दू के मन में अपने हिन्दुस्तान में बेटियों को नहीं बचा पाने का आक्रोश है। इन्हें लव के नाम पर फंसाया जा रहा है। तो ऐसा करने वालों, अपने मुगालते ठीक कर लेना। ड्रग्स माफिया हो या कोई और सबको कुचला जाएगा। जो अपराधियों के साथ हैं, उन सबको कुचला जाएगा।

हर कॉलेज के एंट्री गेट पर लगे कैमरा

उन्होंने कहा कि वे पुलिस कमिश्नर से मांग करेंगे कि राजधानी के हर छोटे होटलों में कैमरे लगाएं और भोपाल पुलिस के कैमरे से कनेक्ट किया जाए। कैफे, छोटे होटलों में कैमरे लगाए जाएं ताकि आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सभी कालेज प्राचार्य और मालिकों को चिट्ठी लिख रहा हूं कि वे अपने कालेज के एंट्री गेट के पास से कालेज भवन तक कैमरे लगाएं। इसे भी भोपाल पुलिस को बताना होगा। कालेज और स्कूल परिसर के आस पास कौन कौन घूम रहा है इसकी जानकारी भोपाल पुलिस के पास रहनी चाहिए।

तो हमारा जिन्दा रहना बेकार

शर्मा ने कहा कि हर हिन्दू में आक्रोश है कि अगर हम अपनी बेटी को नहीं बचा पाए तो हमारा जिन्दा रहना ही बेकार है। अपराधियों को सार्वजनिक सजा भी हो और यह समाज देगा भी। शर्मा ने कहा कि ड्रग्स पर एक्शन के लिए आरिफ मसूद प्रेरित कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।

नारी शक्ति हेल्पलाइन नम्बर जारी

सकल हिंदू समाज द्वारा लव जिहाद की घटनाओं पर जारी नारी शक्ति हेल्प लाइन नंबर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस हेल्प लाइन पर सभी बेटियां संपर्क करें जो इस घटना की शिकार हुई हैं। इस पूरी हेल्पलाइन को बहन-बेटियों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। मेरा बेटियों से आग्रह है, उनके साथ या किसी अन्य बेटी के साथ लव जिहाद जैसी घटना हो तो वह इस हेल्प लाइन पर संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने हेल्प लाइन नंबर जारी करने के लिए सकल हिंदू समाज को बधाई दी।

संपादकीय

पानी को लेकर अशोभनीय विवाद

जहां एक तरफ भारत सरकार ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश के दो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे को लेकर जिस तरह की तनातनी, दोषारोपण और घटिया राजनीति हो रही है, वह अशोभनीय और चेतावनी भरा है। इस गहराते विवाद को मोदी सरकार को प्राथमिकता से ध्यान देकर हल करना चाहिए। वरना दोनो राज्यों में टकराव हिंसा में भी बदल सकता है।

दरअसल पंजाब सरकार ने पिछले समझौते का उल्लंघन करते हुए भाखड़ा नंगल बांध से हरियाणा को दिया जाने वाला पानी आधा कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। लिहाजा वो हरियाणा को एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं देंगे। पंजाब का यह भी आरोप है कि केन्द्र सरकार के नियंत्रण वाले भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी आवंटित करके गलत फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह 'पंजाब के हक पर डकैती है। उधर ज्यादा पानी की मांग कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम मान पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। इस बीच दोनों राज्यों में पानी को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भाखड़ा और पोंग बांधों से अपनी सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए पानी प्राप्त करते हैं, जिनका प्रबंधन बीबीएमबी करती है। हर साल 21 मई से इन तीनों राज्यों के लिए पानी का कोटा तय किया जाता है। इस साल बीबीएमबी ने राजस्थान को 3.318 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ), हरियाणा को 2.987 एमएएफ और पंजाब को 5.512 एमएएफ पानी आवंटित किया है। जबकि पंजाब का दावा है कि हरियाणा ने मार्च में ही अपनी हिस्सेदारी का 103 प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर लिया था और अब वह पंजाब के हिस्से पर नजर गड़ाए हुए है। उधर पंजाब के रवैये से परेशान हरियाणा ने कहा कि उनके प्रदेश में 11,567 ट्यूबवेल हैं, जिनके जरिए पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। दो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद की जड़ें करीब 60 पुरानी है, जब 1966 में इंदिरा गांधी अवॉर्ड के तहत पंजाब से अलग कर हरियाणा राज्य बनाया गया। तभी से सतलुज और ब्यास नदी के पानी को दोनो राज्यों के बीच बंटवारा विवाद का बिंदु रहा है। भारत-पाक के बीच 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत तीन नदियों सतलज, रावी और व्यास नदी का पानी भारत को आवंटित किया गया। इसके बाद 1981 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच व्यास नदी पर बने भाखड़ा नंगल बांध के पानी का बंटवारा तय हुआ। समझौते के तहत व्यास नदी के अतिशेष 17.17 मिलियन एकड़ फीट (एमएफ) पानी में से पंजाब को 4.22 एमएफ, हरियाणा को 3.50 एमएएफ तथा राजस्थान को 8.60 एमएएफ पानी देना तय हुआ। इसके अगले साल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव में सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया। यह नहर 214 किमी लंबी बननी थी, जिसका 122 किमी हिस्सा पंजाब में और बाकी 92 किमी भाग हरियाणा में है। लेकिन अकाली दल ने इसका विरोध किया। बाद में हरियाणा ने तो अपने हिस्से की नहर बना ली, लेकिन पंजाब का काम अभी भी अधूरा है। इस बीच मामला इराडी ट्रिब्यूनल तक गया। ट्रिब्यूनल ने 1987 में फैसला दिया कि इस नहर से पंजाब को 5 एमएएफ तथा हरियाणा को 3.83 एमएएफ पानी दिया जाए। इसी के तहत हाल तक पंजाब हरियाणा को 9500 क्यूसेक पानी रोजाना दे रहा था, लेकिन अचानक पंजाब ने इसमें आधी कटौती कर इसे 4000 क्यूसेक कर दिया।

आतंकवाद से संघर्ष में पहलगाम आगे

नजरिया

अवधेश कुमार

लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भी आंतरिक और सीमा पार आतंकवाद के समूल नाश का सक्रिय संकल्प दिखाया है। मोदी सरकार ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक तथा 2018 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई बमबारी जैसी भारत की दृष्टि से अकल्पनीय माने जाने वाली कार्रवाई करके देश का विश्वास प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी की आमसभा में केवल आतंकवादी के साथ उने सरपरस्तों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की घोषणा की जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। बिहार की भूमि पर उन्होंने कुछ मिनट अंग्रेजी में भाषण दिया जो विश्व के लिए संदेश था कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत कमर कस चुका है और कार्रवाई करेगा।

पहलगाम हमले के बाद संपूर्ण देश का सामूहिक मानस वैसी कार्रवाई, प्रतिरोध और प्रतिशोध का है जिससे भारत को दोबारा ऐसी भयानक घटना का सामना न करना पड़े। यह स्वाभाविक है। एक समय जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं आम थी और तब भी लोगों के अंदर क्रोध पैदा होता था लेकिन आम मानस यह था कि इसे रोकना अभी संभव नहीं। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बाद माहौल बदला, आतंकवादी घटनाओं में व्यापक कमी आई है, कश्मीर घाटी भी धीरे-धीरे आर्थिक-सामाजिक -सांस्कृतिक -शैक्षणिक गतिविधियों में देश के सामान्य राज्य की तरह काफी हद तक पटरी पर लौटा है। ऐसे माहौल में हिंदू होने के कारण 26 हिंदुओं तथा एक गैर मुस्लिम का उनका विरोध करने के कारण हत्या के बाद उबाल स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भी आंतरिक और सीमा पार आतंकवाद के समूल नाश का सक्रिय संकल्प दिखाया है। मोदी सरकार ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक तथा 2018 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई बमबारी जैसी भारत की दृष्टि से अकल्पनीय माने जाने वाली कार्रवाई करके देश का विश्वास प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी की आमसभा में केवल आतंकवादी के साथ उने सरपरस्तों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की घोषणा की जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। बिहार की भूमि पर उन्होंने कुछ मिनट अंग्रेजी में भाषण दिया जो विश्व के लिए संदेश था कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत कमर कस चुका है और कार्रवाई करेगा। इस भाषण से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया गया और इसका असर भी है।

कोई देश सार्वजनिक संकल्प दिखाते हुए समानांतर कदम उठाता है और उसकी पृष्ठभूमि आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की हो चुकी है तो विश्व समुदाय को भी सोच और व्यवहार को उसके अनुरूप बदलना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ एक देश नहीं खड़ा है। वे मुस्लिम देश, जो सामान्यतः जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक सम्मेलन संगठन या ओआईसी में उसका साथ देते थे, हिम्मत नहीं दिखा रहे। अमेरिकी विदेश विभाग की ब्रीफिंग में एक पाकिस्तानी पत्रकार के प्रश्न की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हिकारत के भाव से उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस पर भारत के साथ हैं। सच है कि काश पटेल के नेतृत्व में अमेरिका की एफबीआई तथा तुलसी गवार्ड के निर्देशन में नेशनल इंटेलिजेंस आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत के साथ खड़ा है। यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने यद्यपि इस्लामाबाद में 26 देश के राजनयिकों को बुलाकर अपनी दृष्टि से ब्रीफिंग की किंतु कोई उससे प्रभावित है ऐसा लगता नहीं। प्रश्न है कि भारत क्या कर सकता है, क्या करेगा और कैसी संभावनाएं हैं?

घटना के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की

समिति ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानियों को दिये हर तरह का वीजा रद्द करने, उन्हें देश छोड़ने, पाकिस्तानी उच्चायोग से रक्षा और सैनिक विभाग के अपने समकक्षों को इस्लामाबाद से बुलाने तथा संख्या कम करने का कदम उठाया। इसके साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। पाकिस्तान ने इसकी प्रतिक्रिया में सीनेट में प्रस्ताव पारित किया तथा आतंकवादी घटना से स्वयं को अलग करते हुए भारत पर ही बदनाम करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान का वक्तव्य है कि सिंधु जल समझौते को रद्द करना युद्ध जैसा कदम है। उसने 1972 के शिमला समझौता को समाप्त करने की धमकी दी। पाकिस्तान की दुर्दशा देखिए कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में आतंकी संगठनों के वित्त पोषण , प्रशिक्षण और समर्थन के इतिहास संबंधी प्रश्न पर स्वीकार किया कि हम अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए ऐसा करते रहे हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम अगर सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान युद्ध या 9/11 में साथ नहीं होते तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहता। यह भी वास्तविक सच को इस मायने में झूठलाना है क्योंकि स्थिति का लाभ उठाते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान ने अपनी ओर से प्रायोजित किया और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो एक हद तक अभी भी कायम है। विश्व के प्रमुख देशों की सूचना में ये सारी बातें हैं। इसलिए भारत ने जब 2018 में हवाई बमबारी की तो एक भी देश ने उसका विरोध नहीं किया। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे।

देश में पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई या युद्ध का माहौल बना हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई बमबारी किया जा चुका है तथा इसके प्रभाव भी पड़े। स्वाभाविक ही इससे बड़ी कार्रवाई की स्थिति सामने है। तो आगे क्या? जम्मू कश्मीर के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता थी जो हो रही है। भारत ने आंतरिक रूप से पहलगाम हमले के एक आतंकवादी सहित सहयोग करने वाले संलिप्त नौ लोगों का घर ध्वस्त कर दिया गया। यह आतंकवादियों को सीधा संदेश है कि भारत बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में न केवल भारत बदला है बल्कि जम्मू कश्मीर तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी बदल है। यह पहली बार है जब आतंकवादी घटना के विरुद्ध कम या ज्यादा संख्या में संपूर्ण जम्मू कश्मीर से लोग सड़कों पर आए हैं, कैंडल मार्च और छोटे-मोटे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। यह सब गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के बाद ही आरंभ हुआ। अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस ने पहली बार जिले - जिले में विरोध प्रदर्शन किया और महबूबा मुफ्ती जैसी आतंकवाद की समर्थक और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख वाली को भी सड़क पर उतरना पड़ा। कश्मीर में जहां आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा कार्रवाई के विरुद्ध नारे लगाते थे, पत्थरबाजी होती थी और आतंकवादियों के निकल भागने का रास्ता तैयार किया जाता था उसके विपरीत ये दृश्य बदलाव के संदेश हैं।

थोड़ी गहराई से विचार करें तो निष्कर्ष आएगा कि सीमा पार सैन्य कार्रवाई को छोड़कर जितने कदम उठाए जा सकते थे लगभग भारत ने उठा लिया है। इसका अर्थ है कि भारत समग्रता में दीर्घकालिक समाधान की दृष्टि से बहुपक्षीय कार्रवाई की ओर अग्रसर है। सिंधु जल संधि पर भारत ने 25 अप्रैल को स्पष्ट किया कि वह एक-एक बूंद पानी रोकेगा और उसके लिए तात्कालिक , मध्यवर्ती और दीर्घकालिक उपाय के संकेत दिए गए। यह काफी हद तक संभव है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला दौरा हुआ जहां उन्होंने दो प्रमुख सैन्य मुख्यालयों विक्टर फोर्स और चिनार कोड में वरिष्ठ कमांडरों से बातचीत की तथा नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से हुई गोलीबारी को भी समझा। पहले सेना अध्यक्ष और उसके बाद के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। सैन्य कार्रवाई या युद्ध के पहले तैयारी करनी होती है। सेना को लक्ष्य दिया जाता है और उसके अनुरूप रणनीति बनाते हुए संघर्ष करती है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जैसा बाद में जनरल मानेक शा ने बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मई-जून में सैन्य कार्रवाई के लिए कहा। मानेक शा ने तैयारी के लिए लगभग 6 महीने का समय लिया और दिसंबर में भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया।

यह समझना होगा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर ने 17 अप्रैल के अपने भाषण में न केवल पाकिस्तान सेना, वहां के सुरक्षा बल और आतंकवादी बल्कि आम मुसलमान को भी जेहाद के लिए पूरी तरह उकसाया है। ये सच मायने नहीं रखने कि आसिफ मुनीर सेना में अपने विरुद्ध असंतोष, इमरान खान की पार्टी को नियंत्रित करने, अफगानिस्तान के साथ तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने एवं देश के अंदर सेना पर भ्रष्टाचार, काहिली, विफलता और अय्याशी के लग रहे आरोपों का खंडन करने में विफल साबित हुए हैं। आतंकवाद के हथियार से संघर्ष करने के लिए राजनीतिक - आर्थिक स्थिरता तथा शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं। पाकिस्तान की विचारधारा से जुड़े मुसलमानों के एक समूह के अंदर भी जम्मू कश्मीर को इस्लामी जेहाद का भाग बनाने की भावना पैदा है तो उससे केवल परंपरागत सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का हवाला दिया है। मोदी सरकार की पहले की दो कार्रवाइयों से पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल चुकी है। तो निश्चित मानिए पाकिस्तान के विरुद्ध बहुपक्षीय निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन अपने देश के अंदर प्रभावी इकोसिस्टम अभी से सरकार ही नहीं संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध नैरेटिव खड़ा करने में लगा है उसका भी प्रभावी रूप से सामना करना होगा।

समाज कल्याण और नीति निर्माण के लिए हो उपयोग

जातिगत जनगणना

संदीप सृजन

लेखक स्तंभकार हैं।

जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है जो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है। यह न केवल सामाजिक संरचना को समझने का एक उपकरण है, बल्कि नीति निर्माण और संसाधन वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जातिगत जनगणना को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, न कि समाज को विभाजित करे। यदि इसे सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाए, तो यह भारत को एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सकता है।

जातिगत जनगणना का इतिहास भारत में औपनिवेशिक काल से शुरू होता है। भारत में पहली बार व्यापक जनगणना 1881 में ब्रिटिश शासन के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें जाति के आधार पर भी आंकड़े एकत्र किए गए। यह प्रक्रिया 1931 तक नियमित रूप से हर दस साल में दोहराई गई। 1931 की जनगणना में विभिन्न जातियों और उपजातियों की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई, जो आज भी कई नीतियों और आरक्षण प्रणालियों के लिए आधारभूत डेटा के रूप में उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, 1931 के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 1980 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी।

1941 की जनगणना में भी जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य प्रशासनिक कारणों से इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आजादी के बाद, 1951 की जनगणना में भारत सरकार ने जातिगत आंकड़े एकत्र करने को बंद करने का निर्णय लिया। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का मानना था कि जातिगत जनगणना सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा सकती है और राष्ट्रीय एकता के लिए यह हानिकारक हो सकती है। इस निर्णय के बाद, केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंकड़े एकत्र किए जाने लगे, जबकि अन्य जातियों के लिए कोई अलग डेटा संग्रह नहीं किया गया।

हालांकि, समय के साथ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और नीति निर्माण में सटीक डेटा की आवश्यकता ने जातिगत जनगणना की मांग को फिर से प्रबल किया। 2011 में, यूपीए सरकार ने सामाजिक- आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) आयोजित की, जो 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित डेटा संग्रह का प्रयास था। लेकिन इस सर्वेक्षण के आंकड़े पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए, और इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे।

हाल के वर्षों में, विशेष रूप से बिहार में 2023 में आयोजित जाति आधारित सर्वेक्षण ने इस मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। बिहार सरकार ने इस सर्वेक्षण को दो चरणों में पूरा किया, जिसमें पहले चरण में घरों की गिनती और दूसरे चरण में जातियों के आंकड़े एकत्र किए गए। केंद्र सरकार ने शुरू में इस सर्वेक्षण का विरोध किया, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। 2025 में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अगली राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) ने मंजूरी दे दी है।

जातिगत जनगणना के समर्थक इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। जातिगत जनगणना से विभिन्न जाति समूहों की शिक्षा, रोजगार, आय और संपत्ति के वितरण में असमानताओं का सटीक आकलन किया जा सकता है। यह डेटा नीति निर्माताओं को उन समुदायों की पहचान करने में मदद करता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक हाशिए पर हैं। उदाहरण के लिए, बिहार के 2023 सर्वेक्षण ने दिखाया कि 84 प्रतिशत आबादी सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर है, जिसने नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण को जन्म दिया।

सटीक जाति आधारित डेटा के आधार पर सरकारें विशिष्ट समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष जाति समूह में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो उनके लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट हो सकता है कि किन क्षेत्रों या समुदायों में संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सकता है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। वर्तमान में OBC आरक्षण 1931 के आंकड़ों पर आधारित है, जो अब पुराने और अप्रासंगिक हो चुके हैं। जातिगत जनगणना से नया डेटा मिलेगा, जिसके आधार पर आरक्षण कोटे को समायोजित किया जा सकता है। जातिगत जनगणना शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान डेटाबेस प्रदान कर सकती है, जिससे सामाजिक गतिशीलता, असमानता और विकास के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन संभव हो सकता है। जातिगत जनगणना से वंचित समुदायों को उनकी स्थिति सुधारने का अवसर मिलेगा, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होगी और लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी।

जातिगत जनगणना के विरोधी इसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हानिकारक मानते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत जनगणना से समाज में जातिगत तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। यह लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर समूहों में बांट सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंच सकता है। जातिगत जनगणना में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाती है, जिसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। यदि यह डेटा गलत हाथों में पड़ता है, तो यह सामाजिक भेदभाव को और बढ़ा सकता है।

2025 में केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना को अगली राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के फैसले ने इस मुद्दे को नया आयाम दिया है। यह निर्णय बिहार जैसे राज्यों में हुए सर्वेक्षणों और विपक्षी दलों की लगातार मांगों के दबाव में लिया गया है। बिहार के 2023 सर्वेक्षण ने दिखाया कि कैसे जाति आधारित डेटा नीति निर्माण में उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव को भी उजागर किया।

विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना एक दोधारी तलवार है। एक ओर, यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह उन समुदायों को मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। दूसरी ओर, इसके गलत उपयोग से सामाजिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और जातिगत पहचान को और मजबूत करने का खतरा है।

जातिगत जनगणना भारत जैसे विविध और जटिल समाज में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका इतिहास औपनिवेशिक काल से शुरू होकर आज के आधुनिक भारत तक फैला हुआ है, जहां यह सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इसके लाभ, जैसे कि नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और सामाजिक समानता, इसे एक आवश्यक उपकरण बनाते हैं। हालांकि, इसके नुकसान, जैसे कि सामाजिक विभाजन, डेटा दुरुपयोग और प्रशासनिक चुनौतियां, इसे विवादास्पद बनाते हैं।

इसलिए, जातिगत जनगणना को लागू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, डेटा संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी और गोपनीय बनाया जाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन न हो। दूसरा, आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। तीसरा, जनगणना के परिणामों को केवल सामाजिक कल्याण और नीति निर्माण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए।

ताबूत से बाहर मन

कटाक्ष

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हम सभी अलग अलग अपने अपने ताबूतों में बंद उस राजनेता के आने का इंतजार कर रहे थे जो हमें बस कुछ ही देर में श्रद्धांजलि देने आने ही वाले थे। हमारे ऊपर चढ़ाये जाने वाले पुष्प चक्र एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे।साफ़ दिख रहा था कि उनकी स्थिति अस्पताल में पड़ी हुई हमारी लाशों से कहीं बेहतर थी। बगल के ताबूत वाले ने कहा-तुम तो डेढ़ घंटे जीवित रहे।समय पर सहायता मिल जाती तो शायद बच जाते।अफ़सोस कोई लोकल मीडियामेन भी आ जाता तो मेन स्ट्रीम को तुमसे दो तीन दिन चलाने लायक बाइट मिल जाती।हादसे में मरे लोगों में से देर तक जीवित बचे आदमी का आखिरी इंटरव्यूह।

मैंने कहा-तुम भी थोड़ा रुक जाते।तुम्हें कौन सी जल्दी थी? आई पी एल का मैच देखना था या बिहार की रैली? वो शायद आम आदमी था इसलिए आम आदमी की तरह सुनकर चुप रह गया। माहौल में सन्नाटा पसरा था कुछ हादसे की गंभीरता के कारण और कुछ आने वाले बड़े नेता की उपस्थिति से उपजने वाले भय के कारण। वहां तैनात कर्मियों की छोटी सी चूक से उनकी नौकरी जा सकती है शायद इस खौफ के कारण भी।

हमारे शव सरकारी खर्च पर अलग अलग प्रदेशों में ले जाने के लिए चार्टर प्लेन तैयार खड़े थे ताकि जैसे ही नेताजी श्रद्धांजलि देकर फारिग़ हों जुरंत उड़ान भरकर हमारे शव हमारे शेक संतप्त परिजनों को सौंपे जा सकें।वैधानिक रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी यहीं तक थी। यद्यपि हमारी मृत्यु पर आर्थिक रूप से मुआवजे की घोषणा हो चुकी थी परन्तु परिजनों को कब मिलेगा ये बात कोई नहीं जानता।हो सकता है हमारा अगला जन्म होने तक भी न मिले, और उसके बाद भी न मिले तो हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो आकर गुहार लगाने से रहे। आगमन स्थल से लेकर ताबूतों तक लाल कालीन बिछा था। अगवानी को छोटे बड़े अफसर और सुरक्षा बल तैनात था जो उस समय मरने वालों को उपलब्ध न हो सका।वातावरण में नेताजी की संभावित उपस्थिति की अतिरिक्त गरिमा थी।अनायास हवा में धीमी आवाज़ में देश भक्ति के गाने सरसराने लगे जो निश्चय ही उनके आने के सूचक थे।फलतः देश भक्ति और राष्ट्र प्रेम जातिवाद और साम्प्रदायिकता की तरह मिल जुलकर हवा में तैरने लगे।

आने वाले नेताजी ऐसी घटनाओं के अभ्यस्त थे। सफेद कलफ़दार कुर्ता पायजामा और काली जाकिट पहने उन्होंने निर्विकार भाव से पंक्तिबद्ध ताबूतों के आगे रुक रुककर हाथ जोड़े और सहयोगी के हाथ से लेकर क्रमशः पुष्पचक्र चढ़ाये। यही करते करते आगे वे बढ़ते गये । दूसरे छोर पर उनकी गाड़ी तैयार थी उनको वापिस ले जाने के लिए।उन्हें अभी देश दुनिया के बहुत से काम निबटाने थे। जरूरी फाइलें और हादसे के कारण आयोजित आकस्मिक बैठकें भी।देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न जो था।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस पर भी लिखो!

व्यंग्य

सचिन सिंह परिहार

(लेखक एवं राष्ट्रीय कराते खिलाड़ी)

जब तक मैं लेखक नहीं था, तब तक मैं भी एक आम आदमी था–जो गर्मी में पसीना बहाता, सर्दी में रज़ाई में दुबकता, दुख में रोता और मज़ाक में हँसता था। पर जैसे ही मेरे कुछ लेख अख़बार में छपे, मोहल्लेवालों ने मेरी पहचान बदल दी–लो भई, ये लेखक भी है!

अब हाल यह है कि मेरी ज़िंदगी की हर घटना, हर क्षण, हर ठोकर–एक संभावित लेख बन चुकी है।

चाय का कप गिरा, तो चावड़ा जी बोले–इस पर ज़रूर लिखो! गिरती चाय और समाज की गिरती संवेदनाएं–क्या प्रतीक मिलेगा!

मोहन का मोबाइल फर्श पर गिरा, तो भाटी जी उछले–बड़ी बात है भाई! 'गिरती टेक्नोलॉजी, गिरता इंसान' टाइप टाइटल रखो!

पटेल साहब की बेटी की शादी में जूते चोरी हुए, तो सोनू बोला–'जूते चुराई और चरित्र की सच्चाई'–इस पर भी तीखा व्यंग्य बनाओ!

अब तो आलू खरीदने जाओ, तो सब्ज़ीवाला बोलता है, महंगाई बहुत है, साहब।

मैंने सिर हिलाया ही था कि बगल से भारती भाभी फुसफुसाई–'आलू का दर्द' लिखिए न! बहुत भाव निकलेगा!

मैंने कहा,भाभी, अभी तो बस आलू ले रहा हूँ।

वो बोलीं, तो क्या हुआ? लेखक हो, हर अनुभव लेख है!

अब हालत ये हो गई है कि मोहल्ले के कुत्ते भी मुझसे डरते हैं। गाड़ी के नीचे बैठे पांच कुत्तों को देखकर सोनी जी बोले–'कुत्ता संवाद सम्मेलन' पर लिखिए। लोकतंत्र और कुत्तों में क्या फर्क रह गया है!

घर में बहस हुई कि पंखा दो नंबर पर चले या तीन पर।

पत्नी ने तरेरी आँखें, हर बात पर लिखते हो, इस पर क्यों नहीं?

मैं मुस्कुराया, अगर इस पर लिखा, तो अगली बार शायद चाय भी न मिले।

(इसके बाद से घरेलू मामलों पर मैंने मौन व्रत ले लिया है।)

घूमने गया तो दोस्त बोले–ध्यान से चलना, लेखक साथ है। कुछ भी किया, अख़बार में छप जाएगा।

एक बोला–भाई, तू सीसीटीवी है क्या? पिछली बार दारोग़ा अंकल को हूबहू उतार दिया था!

अब तो सड़क पर फिसलना हादसा नहीं, लेख का प्लॉट है।

भोजन में नमक कम हो, तो कहते हैं–अब 'बिना नमक का समाज' टाइप लेख आना चाहिए।

सरकार कोई बिल पास न करे, तो लोग मुझे घूरते हैं–अब बताओ लेखक जी, क्या कहेंगे इस पर?

जंगल पार्टी में नेटवर्क नहीं आया, तो भाटी जी फिर बोले–'लेखन और नेटवर्क'–वाह! समाज से कटते संवादों पर व्यंग्य चाहिए!

बैंक में घंटों लाइन में खड़ा रहा। जैसे ही नंबर आया, कंप्यूटर बंद।

पीछे से पंडित शर्मा बोले–अब तो लेख बनना तय है–'बैंक और बंद भाग्य!'

अब लोग मुझे लेखक नहीं, चलता-फिरता कीबोर्ड समझते हैं।

जो बोले इस पर भी लिखो–वो भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ। हर जगह नोट्स नहीं बनते।

कभी सोचता हूँ कि लोग वाकई पढ़ते भी हैं, या बस लिखो कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं।

हद तो तब हुई जब सपने में लेख लिख रहा था, और सपने में ही लोग कह रहे थे–अब इस सपने पर भी लिखो!

सुबह उठा तो सोचा–अबकी बार नहीं लिखूँगा।

पर आप ये पढ़ ही रहे हैं, मतलब फिर लिख ही दिया।

अब जब अगली बार कोई कहे–इस पर भी लिखो–

तो मैं कहूँगा–ज़रूर लिखूँगा लेकिन अगली बार तुम्हारा किरदार थोड़ा बेहतर लिखवाना पड़ेगा, वरना फिर से भाटी जी ही हीरो होंगे!

विचार

सुरेश रायकवार

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या यह गीतोपदेश के पालन का समय है?

12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, न्याय और मीमांसा सहित समस्त शास्त्रों में पारंगतता हासिल कर ली थी। उन्होंने न केवल अद्वैत वेदांत को सैद्धांतिक रूप से पुष्ट किया बल्कि देश के कोने-कोने में जाकर उसे जीवन पद्धति के रूप में स्थापित भी किया। उनकी यात्रा केवल बौद्धिक नहीं थी बल्कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की भी यात्रा थी। उन्होंने भारत की विविध धाराओं को एकताबद्ध करते हुए सिद्ध कर दिखाया कि सनातन धर्म केवल रीति-नीति नहीं बल्कि जीव और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का आत्मबोध है। आदि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जो कहता है कि 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म का ही रूप है।

हाल ही पहलगाम में हुई पाक प्रायोजित आतंकी घटना के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कट्टरतावादी बयान तथा आजादी के बाद से बार-बार आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश की शांति भंग करने के पाकिस्तानी प्रयास को क्या अब वाकई विराम देने का समय आ गया है? प्रश्न यही है कि हम हमारी सहिष्णुता और नम्रता को आखिर कब तक उस नापाक को कमजोरी समझने का अवसर देते रहेंगे? ऐसे में श्रीमद भगवद्गीता जिसका प्रत्येक उपदेश पालन योग्य है और जिसे वेद और उपनिषदों का सारांश भी कहा जाता है, अत्यंत प्रासंगिक और अनुकरणीय है। श्रीमद्भगवत गीता दुनिया का एक सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमे हमारे व्यक्तिगत प्रश्नों से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैश्विक सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। गीता विश्व में एकमात्र धर्म ग्रंथ होगा जिसमे भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हे भी कर्म करना पड़ते है और धर्म के रक्षार्थ यही उपदेश व्यक्ति को आलस और प्रमाद त्यागकर कर्म करने को प्रेरित करता है।

अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष युद्ध ना करने के लिए कई तर्क रखे (जैसे आज हमारे देश की कई राजनैतिक पार्टियां अपने तर्क-वितर्क से जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा करती है) और युद्ध करने से स्पष्ट मना कर दिया। तब भगवान ने उसे शास्त्र सम्मत तत्व समझा कर ना केवल युद्ध को आवश्यक बताया बल्कि उसे धर्मयुद्ध भी निरूपित किया। ऐसा नहीं है कि भगवान श्रीकृष्ण ने युद्ध को टालने के प्रयास नहीं किए, स्वतंत्रता के बाद से ही हमारा देश भी लगातार युद्ध को टाल ही रहा हैं, फिर भी शत्रु की ओर से अब तक 1965, 1971 और कारगिल जैसे युद्ध तो थोपे ही गए साथ में 26/11 और पुलवामा नरसंहार जैसे आतंकी हमले भी किए गए हैं। दुर्योधन की ही तरह पीओके में पाकिस्तान ने हमारे देश की भूमि पर भी अनाधिकृत अन्यायपूर्ण कब्जा कर रखा है।

भगवान श्रीकृष्ण ने इस महान ग्रंथ में ज्ञानयोग, कर्मयोग, सन्यासयोग, भक्तियोग के उपदेश के साथ-साथ अर्जुन को वर्णधर्म, आहार, यज्ञ, तप और दान, श्रद्धा, ध्यान, मन का निग्रह, ब्रह्म, अध्यात्म, जगत की उत्पत्ति, उपासना, ईश्वर की विभूतियाँ, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, प्रकृति-पुरुष, सत्व रज और तमगुण, संसार वृक्ष, दैवीय एवं आसुरी वृत्ति, त्याग, कर्म, कर्ता, बुद्धि और घृती आदि विषयों को माध्यम बनाकर ना केवल युद्ध की अनिवार्यता को समझाया बल्कि निम्न श्लोकों में तो स्पष्टता से उसे युद्ध की अपरिहार्यता भी समझाई है :

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते।।2.31।।

अर्थात, अपने धर्म (क्षत्रिय धर्म) को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानि तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है।

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।।2.32।।

अर्थात, हे पार्थ! अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं।

अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।।2.33।।

अर्थात, किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा।

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्।
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते।।2.34।।

अर्थात, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है।

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।।2.35।।

आशय यह कि, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे।

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्।।2.36।।

अर्थ यह कि तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; उससे अधिक दुख और क्या होगा?

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।।2.37।।

अर्थात, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन! तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।।2.38।।

अर्थात, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।।3.30।।

अर्थात, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सम्पूर्ण कर्मों को मुझमे अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर।

यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।।18.59।।

जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूंगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्ध में लगा देगा।

भगवान ने गीता में कई स्थान पर अर्जुन को भारत भी संबोधित किया है आज हमारे भारत देश के सामने भी लगभग वही स्थिति-परिस्थिति हैं जिनके लिए महाभारत का धर्मयुद्ध लड़ा गया था। यह समय इस शास्त्र को अन्य धार्मिक पुस्तकों की तरह केवल पूजने का नहीं, बल्कि उसके ईश्वरीय ज्ञान और उपदेशों के उपयोग का समय है।

प्यासे सहरिया

आरती पाराशर

पानी के लिए चलना, अधिकारों के लिए इंतजार

संस्था विकास संवाद और क्राय नई दिल्ली के सहयोग से सहरिया समुदाय द्वारा अप्रैल 2025 में किए गए एक सामुदायिक आधारित सर्वेक्षण में शिवपुरी जिले के 15 सहरिया-बहुल गांवों को शामिल किया गया। यह सर्वेक्षण 'कम्युनिटी-बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ़ माल न्यूट्रीशन प्रोजेक्ट/कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन परियोजना' के अंतर्गत किया गया था, जिसमें मुख्य उद्देश्य गांवों में पेयजल स्रोतों की स्थिति का आकलन, महिलाओं और बच्चों पर जल संकट के प्रभाव की पड़ताल, योजनाओं (जैसे जल जीवन मिशन) की प्रगति की समीक्षा, और समुदायों की सामूहिक आवाज़ और रणनीतियों का मूल्यांकन करना था। सर्वेक्षण के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जिले के सहरिया गांवों में पानी की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित है, और जल संकट का समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक के कई सहरिया गांवों में जल संकट अब जीवन संकट बन चुका है। पानी की कमी सिर्फ एक भौगोलिक समस्या नहीं है, बल्कि यह समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका और गरिमा से जुड़ा एक गंभीर मानवाधिकार संकट है। शिवपुरी जिले में पानी की भारी कमी एक स्थायी समस्या बन चुकी है। विशेष रूप से गर्मी के महीनों में जल स्रोत सूख जाते हैं, जिससे गांववासियों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, जिन्हें परिवार की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात संघर्ष करना पड़ता है।

संस्था विकास संवाद और क्राय नई दिल्ली के सहयोग से सहरिया समुदाय द्वारा अप्रैल 2025 में किए गए एक सामुदायिक आधारित सर्वेक्षण में शिवपुरी जिले के 15 सहरिया-बहुल गांवों को शामिल किया गया। यह सर्वेक्षण 'कम्युनिटी-बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ़ माल न्यूट्रीशन प्रोजेक्ट/कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन परियोजना' के अंतर्गत किया गया था, जिसमें मुख्य उद्देश्य गांवों में पेयजल स्रोतों की स्थिति का आकलन, महिलाओं और बच्चों पर जल संकट के प्रभाव की पड़ताल, योजनाओं (जैसे जल जीवन मिशन) की प्रगति की समीक्षा, और समुदायों की सामूहिक आवाज़ और रणनीतियों का मूल्यांकन करना था। सर्वेक्षण के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जिले के सहरिया गांवों में पानी की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित है, और जल संकट का समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

माचाखुर्द गांव के निवासी रमेश बताते हैं, 'गर्मी में हमारी बावलियाँ सूख जाती हैं, और हमें पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है।' पानी लाने के लिए महिलाएं और बच्चे अक्सर 2-3 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद होता है और वे अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा नहीं कर पाते। 'हमारे पास समय नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और हम अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पा पाते,' यह कहती हैं फूलवती, जो माचाखुर्द की निवासी हैं। महिलाओं की यह संघर्षपूर्ण स्थिति केवल घर की देखभाल तक सीमित नहीं रहती; यह उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजीविका को भी प्रभावित करता है। सोनिपुरा गांव में पानी के स्रोत सूखने के कारण वहां के निवासियों को गंदे पानी का सेवन करना पड़ता है। स्थानीय निवासी बनवारी कहते हैं, 'हमें 2 किलोमीटर दूर पानी लाने जाना पड़ता है और रास्ते में पानी के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। इस समय की बर्बादी से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है।'

नल-जल योजना की स्थिति में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि इन योजनाओं के तहत केवल 9 गांवों में जल आपूर्ति शुरू हुई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।इइसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। पानी लाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों पर होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग्राम सभा की भूमिका और भविष्य की दिशा समुदाय के स्तर पर जल संकट को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम सभा की बैठकों में जल संकट को लेकर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों में जल जीवन मिशन और नल जल योजनाओं का कार्यान्वयन, जल आपूर्ति में नियमितता, और पानी के वितरण में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसके अलावा, गर्मी में जल टैंकर की नियमित आपूर्ति और जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

जल समस्या का मूल केवल पानी की नहीं, प्राथमिकता की भी कमी है। यह संकट सिर्फ बारिश की कमी या भूजल स्तर गिरने की वजह से नहीं है। यह संकट इसलिए भी है कि सरकारी योजनाएं बिना क्रियान्वयन के घोषित हो जाती हैं। पंचायत स्तर पर प्राथमिकता सूची में पानी सबसे नीचे होता है। योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी और निगरानी नहीं होती है।

इस अध्ययन ने सुझाया है कि जल जीवन मिशन का सामाजिक ऑडिट कराया जाए। जल टैंकर की नियमितता और स्रोतों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पानी उपलब्ध करवाया जाए।जल संकट समाधान के लिए ग्राम स्तरीय जल समिति को सक्रिय किया जाए। जल संकट समाधान और जल संरचना संरक्षण अभियान चलाए जाएं, जिसमें महिलाएं नेतृत्व करें।

शब्द हिंसा

प्रो.संजय द्विवेदी

लेखक मा. च. रा. पत्रकारिता एवं संचार विवि, भोपाल में जनसंचार विभाग में आचार्य और अध्यक्ष हैं।

जरूरी है मीडिया का भारतीयकरण

यह 'शब्द हिंसा' का समय है। बहुत आक्रमक, बहुत बेलगाम। ऐसा लगता है कि टीवी न्यूज मीडिया ने यह मान लिया है कि शब्द हिंसा में ही उसकी मुक्ति है। चीखते-चिल्लाते और दलों के प्रवक्ताओं को मुर्गो की तरह लड़ाते हमारे एंकर सब कुछ स्क्रीन पर ही तय कर लेना चाहते हैं। यहां संवाद नहीं है, बातचीत भी नहीं है। विवाद और वितंडावाद है। यह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का संवाद नहीं है, आक्रामकता का वीभत्स प्रदर्शन है।

निजी जीवन में बेहद आत्मीय राजनेता, एक ही कार में साथ बैठकर चैनल के दफ्तर आए प्रवक्तागण स्क्रीन पर जो दृश्य रचते हैं, उससे लगता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन कितनी कड़वाहटों और नफरतों से भरा है। किंतु स्क्रीन के पहले और बाद का सच अलग है। बावजूद इसके हिंदुस्तान का आम आदमी इस स्क्रीन के नाटक को ही सच मान लेता है। लड़ता-झगड़ता हिंदुस्तान हमारा 'सच' बन जाता है। मीडिया के इस जाल को तोड़ने की भी कोशिशें नदारद हैं। वस्तुनिष्ठता से किनारा करती मीडिया बहुत खौफनाक हो जाती है।

सूचना और खबर के अंतर को समझिए-

हमें सोचना होगा कि आखिर हमारी मीडिया प्रेरणाएं क्या हैं? हम कहां से शक्ति और ऊर्जा पा रहे हैं। हमारा संचार क्षेत्र किन मानकों पर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया के मानकों के आधार पर खड़ी हमारी मीडिया के लिए नकारात्मकता, संघर्ष और विवाद के बिंदु खास हो जाते हैं। जबकि संवाद और संचार की परंपरा में संवाद से संकटों के हल खोजने का प्रयत्न होता है। हमारी परंपरा में सही प्रश्न करना भी एक पद्धति है। सवालों की मनाही नहीं, सवालों से ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल खोजना है, चाहे वह समस्या मन, जीवन या समाज किसी की भी हो। इस तरह प्रश्न हमें सामान्य सूचना से ज्ञान तक की यात्रा कराते रहे हैं। आज 'सूचना' और 'ज्ञान' को पर्याय बनाने के जतन हो रहे हैं। सच यह है कि 'सूचना' तो समाचार,खबर या न्यूज का भी पर्याय नहीं है। सूचना कोई भी दे सकता है। वह कहीं से भी आ सकती है। सोशल मीडिया आजकल सूचनाओं से ही भरा हुआ है। किंतु ध्यान रखें खबर, समाचार और न्यूज के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। संपादकीय प्रक्रिया से गुजरकर ही कोई सूचना,समाचार बनती है। इसलिए संपादक और संवाददाता जैसी संस्थाएं साधारण नहीं है।

हर व्यक्ति नहीं हो सकता पत्रकार-

यह कहना आजकल बहुत फैशन में है कि इस दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है। हर व्यक्ति फोटोग्राफर है। हर व्यक्ति कम्युनिकेटर, सूचनादाता, मुखबिर हो सकता है, वह पत्रकार कैसे हो जाएगा? मेरे पास कैमरा है, मैं फोटो ग्राफर कैसे हो जाऊंगा। विशेष दक्षता और प्रशिक्षण से जुड़ी विधाओं को हल्का बनाने के हमारे प्रयासों ने ही हमारी मीडिया या संवाद की दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह

वैसा ही है जैसे कपड़े प्रेस करने वाले या प्रिंटिंग प्रेस वाले अपनी गाड़ियों पर 'प्रेस' का स्टिकर लगाकर घूमने लगें। मीडिया में प्रशिक्षण प्राप्त और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना आ रही भीड़ ने अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। लोकमान्य तिलक,महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर, पं.जवाहरलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, माधवराव सप्रे जैसे उच्च शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ और समाज के प्रति समर्पित पत्रकारिता वर्तमान में कहां खड़ी है। भारत सरकार के आग्रह पर प्रेस कौंसिल आफ इंडिया ने पत्रकारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए एक समिति भी बनाई थी, जिसके समक्ष मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर मिला था। बाद में उस कवायद का क्या हुआ पता नहीं।

समाज की रूचि का करें परिष्कार-

समाज की रुचि का परिष्कार और रूचि निर्माण भी मीडिया की जिम्मेदारी है। अपने पाठकों, दर्शकों को समय के ज्वलंत मुद्दों पर अपडेट रखना, उनकी बौद्धिक, नागरिक चेतना को जागृत रखना भी मीडिया का काम है। जबकि देखा यह जा रहा है कि पाठकों की पसंद के नाम पर कंटेंट में गिरावट लाने की स्पर्धा है। ऐसे कठिन समय में मीडिया के दायित्वबोध और सरोकारों पर बातचीत बहुत जरूरी है। प्रिंट मीडिया ने भी साहित्य, कलाओं, प्रदर्शन कलाओं और मनुष्य बनाने वाली सभी विधाओं को अखबारों से निर्वासन दे दिया है। मीडिया सिर्फ दर्शक बना रहे यह भी ठीक नहीं। उसे राष्ट्रीय भावना और जनपक्ष के साथ खड़े रहना चाहिए।

देखा जाए तो समाज में फैली अशांति, स्पर्धा, लालसाओं और संघर्ष के बीच विचार के लिए सकारात्मक मुद्दे उठाने ही होंगे। मीडिया खुद अशांत है और गहरी स्पर्धा के कारण सही -गलत में चुनाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी है कि खुद भी शांत हों और संवाद की शुचिता पर काम करें। वसीम बरेलवी लिखते हैं - कौन सी बात कहां, कैसे कही जाती है। वो सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।

वक्रोक्ति

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

समग्र आहत समाज की परिकल्पना साकार करने की दिशा में

साथियों, आइए हम एक आहत समाज का निर्माण करें। एक ऐसा समाज जहाँ सब एक दूसरे से आहत हैं। यादव कुर्मी से, कुर्मी कोईरी से, कोईरी ब्राह्मण से, ब्राह्मण राजपूतों से, राजपूत बनियों से, एक्स-बनिए वाय-बनियों से, वाय-बनिए ज़ेड-बनियों से...हर कोई हर किसी से आहत घूम रहा है। कितनी अद्भुत है एक समग्र आहत समाज की परिकल्पना। दुनिया के नक़्शे पर एक सौ चालीस करोड़ आहत नागरिकों का यूनिक देश। वी द पीपुल ऑफ़ इंडिया समग्र आहत समाज निर्माण की दिशा में चल तो पड़े हैं मगर यह एक महती और विशाल परियोजना है। अगर आपने इसमें अभी तक अपनी आहुति नहीं दी है तो तैयार हो जाइए। भागीदारी आपको भी करनी है। कैसे ? चलिए, हम आपको बताते हैं।

सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि आहत होना सीख लीजिए। यह बेहद आसान है। आपके पास एक एंड्रायड फोन हो, कुछ जीबी डाटा हो, एक वाट्सअप अकाउंट हो, ढ़ेर सारा फुरसती समय हो। न हो तो बस विवेक न हो। विवेक होना मेजर डिसक्वालिफिकेशन मानी जाती है। अगर संयोग से आपके पास विवेक है तो आहत होने का आव्हान किए जाने पर इसे इस्तेमाल न करें।

घबराएँ बिलकुल नहीं। आपका आहत होना जरूरी तो है, सचमुच में आहत होना बिलकुल जरूरी नहीं है। आप हरबार सचमुच आहत हो भी नहीं सकते क्योंकि आपने तो वो बयान अभी तक देखा, पढ़ा या सुना भी नहीं है जिससे आहत होकर आपने तोड़फोड़ के क्षेत्र में उतरने का फैसला किया है। किसी ने वाट्सअप पर किसी को कुछ भेजा है जो ब्रम्हांड का चक्कर लगाकर आप तक पहुँचा है और आप आहत हो लिए। आपने तो वो किताब पढ़ी भी नहीं जिसके प्रकाशन की खबर मात्र से आप आहत हो लिए। बल्कि, बचपन से ही किताब पढ़ने में आपकी रूचि कभी रही नहीं, आप तो अफवाहभर से आहत हो लिए। किसी ने ट्विटर पर किसी को कुछ कहा है और आप आहत हो लिए। उन्होंने तमिल में कुछ कहा और आप हिंदी में आहत हो लिए। कभी आप गाने के बोल से आहत हो लिए, कभी नायिका के अंतर्वस्त्रों के रंग से। अगला मन ही मन कुछ बुदबुदाया और आप आहत हो लिए। जिसके लिए कहा गया है वो आहत नहीं हुआ, उसके बिहाफ़ पर आप आहत हो लिए। ग्यारहवीं सदी के किसी नायक के लिए किसी ने कुछ कहा, आप ईक्कीसवीं सदी में उनके लिए आहत हो लिए। कभी कभी तो किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा तो भी आप आहत हो लिए। आप इसी से आहत हो सकते हैं कि अमुक जी ने कुछ क्यों नहीं कहा। आहत होने के लिए आपको फैक्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं। आपको तो बस भियाजी के पठ्ठे बने रहना है - वे आपको बताएँगें कि आज आपको इनसे आहत होना है, इनफ।

चलिए आहत हो लिए हैं तो आप वो सब कर पाएँगे जिसकी आज़ादी आपको संविधान से नहीं मिली है, आपने भीड़ बनाकर अपने अख्तियार में कर ली है। मसलन, ज़ेब में चार फूटी कौड़ी न हो मगर इसका या उसका सिर काट लाने पर करोड़ों के ईनाम की घोषणा कर पाने की आज़ादी। प्रदर्शनियों, नाटकों, कवि सम्मेलनों-मुशायरों को तहस नहस कर डालने की आज़ादी। सरेआम गाली-गलौज, मारपीट करने की आज़ादी। आहतकर्ता का मुँह काला करने की आज़ादी।

अब आप इस आज़ादी को एन्जॉय कर सकते हैं। तो ऐसा करें कि जिनसे आहत हुए हैं उनके घर में, ड्राइंग रूम में, स्टूडियो में, प्रदर्शनी में, दफ्तर में या स्टेज पर चढ़कर फर्नीचर तहस नहस कर डालें, लाईटें फोड़ दें, माईक उखाड़ दें, तलवारें और बंदूकें लहराएँ, गर्व करने लायक नारे लगाएँ। शालीनता, शिष्टाचार, शांति, सहिष्णुता और मर्यादा सब कुछ तहस-नहस कर डालिए। आखिर आप आहत जो हुए हैं। आप भरोसे के उस सोशल फेब्रिक को ही तोड़ डालिए जिस पर समाज टिका हुआ है। अगर तब भी अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे तो टारगेट की टांग तोड़ दें, सिर खोल दें। सॉफ्ट हिंसा का सहारा लें यह सेकंड डिग्री का ट्रीटमेंट है। अगर अभी भी अपने आप को हंड्रेड परसेंट अभिव्यक्त न कर पाएँ हों तो 'मॉब लिंचिंग - दी थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट' तो अंतिम उपाय है ही। आप शूरवीर हैं क्योंकि आप उस समूह का हिस्सा हैं जिसने एक निर्दोष निहत्थे अकिंचन जन को मार डाला है। आप उदारवादियों की तरह कायर नहीं हैं। फ़ख्र कीजिए कि आप बुद्धिजीवी भी नहीं हैं। होते तो देशद्रोही कहाते। तोड़फोड़ में गर्व की अनुभूति अंतर्निहित है। आपको नाज़ होना चाहिए कि आप तोड़फोड़ करने के फुल-टाईम कॅरियर में हैं और हर तोड़फोड़ के साथ आपका कॅरियर नई ऊँचाईयों को छू रहा है। आपके पास कमानेवाली नौकरी नहीं है, पेशे में सफलता नहीं है, स्वाभिमानवाला रोज़गार नहीं है, मिलने की संभावना भी नहीं है मगर जातिगत स्वाभिमान पर काँच फोड़ डालने का स्थाई और स्थिर जॉब तो है। जॉब जो आपमें सेंस ऑफ़ फुलफिलमेंट भरता है और अभिव्यक्तिवाली स्वतंत्रता का एहसास कराता है। और हाँ, पुलिस प्रशासन की ओर से निश्चिंत रहें, उसके लिए भियाजी हैं ना। उनके हाथों में नफरत के अलग अलग साइज़-शेप के मारक पत्थर हैं जो वे यथा समय समाज के शांत स्थिर जल में फेंकते रहते हैं। उसे उसके आहत होने का अहसास कराने के मिशन में जुटे रहते हैं। वे समग्र आहत समाज की परिकल्पना को साकार करने में जुटे हैं और आप उनके पठ्ठे हैं।

आहत सेना में आप वर्चुअल वॉरियर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको हथियारों से लैस होकर सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। आपको सोशल मिडिया की आभासी दुनिया में ट्वेंटी-फोर बाय सेवन सक्रिय रहना है, आहत किए जा सकनेवाले मेसेज रिसीव करना है और फॉरवर्ड कर देना है। आपका काम कम मेहनत में ज्यादा असर पैदा करनेवाला है। आपकी एक पोस्ट पूरे समाज को आहत फील करवा पाने का दम रखती है। आप उनमें जोशभर सकते हैं। ललकार सकते हैं। चैलेंज कर सकते हैं। इस या उस रंग का साफा बांधकर तलवार लेकर जुलूस निकाल सकते हैं। तलवार भारी हुई तो बाजुओं में क्रेम्प आ सकते हैं। सावधानी रखें, फोटो खिंचाने जितनी देर ही उठाएँ। नकली तलवार भी उठा सकते हैं। अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता अब सिर्फ आहत नागरिकों के लिए ही बची है।

तो क्या सोचा है आपने ? समग्र आहत समाज के निर्माण में योगदान देने आ रहे हैं ना! प्रतीक्षा रहेगी।

एम्स भोपाल द्वारा नेत्रदान जागरूकता अभियान का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत नेत्र बैंक ने दो दिवसीय नेत्रदान जागरूकता अभियान आयोजित किया। यह अभियान अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, ताकि नर्सिंग स्टाफ को नेत्रदान के महत्व के बारे में बताया जा सके। एम्स भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पखवाड़े के रूप में मनायी जा रही है, और इसी क्रम में ऐसे जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे नर्सिंग समुदाय को सम्मानित किया जा सके और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक पहलों में सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके। इस अभियान में एम्स भोपाल के विभिन्न वार्डों और आईसीयू में काम करने वाले नर्सिंग ऑफिसर, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी और सहायक नर्सिंग अधीक्षक शामिल हुए। उन्होंने नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरकर यह शपथ लिया कि वे न केवल खुद नेत्रदान करेंगे, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे बखूबी निभाते हैं। यह अभियान लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक करने, नेत्रहीनता को कम करने और जरूरतमंद लोगों को नई रोशनी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा, नर्सिंग स्टाफ हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ हैं। जब वे नेत्रदान जैसे नेक कार्यों में भाग लेते हैं, तो समाज को एक सकारात्मक संदेश जाता है। नेत्रदान से किसी की रोशनी लौट सकती है, और ऐसे अभियानों से हम एक जागरूक और संवेदनशील समाज बना सकते हैं। एम्स भोपाल का नेत्र रोग विभाग ऐसे प्रयासों के जरिए समाज में नेत्रदान की भावना को बढ़ावा देने और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

श्री शम्भू दरबार से शोभायात्रा नर्मदा घाट प्रस्थान करेगी

सुबह सवेरे सोहागपुर। विख्यात ब्रह्मलीन संत पंडित मनमोहन मुद्गल के शंम्भू दरबार से आज 3 मई को दोपहर 12 बजे विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी । इस शोभायात्रा में दूरदराज के शंम्भू दरबार के अनुयाई चार पहिया वाहनों से शामिल होकर मां नर्मदा घाट ग्राम सांगाखेड़ा पहुंचेंगे। यहां श्री शिव महाशक्ति महायज्ञ का भूमिपूजन कार्यक्रम संम्पन्न होगा।महायज्ञ 18 से 28 मई 2025 को पूर्ण होगा।आध्यात्म एवं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल के सदस्यों ने बताया कि श्री शिव महाशक्ति महायज्ञ पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन पंडित मनमोहन मुदगल की प्रेरणा से गृहस्थ संत साधक पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल के सानिध्य में संपन्न होगा। यज्ञ समिति सांगाखेड़ा के सदस्यों ने क्षेत्र के समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं से श्री शिव महाशक्ति महायज्ञ के पावन अवसर पर पुण्य कार्य में शामिल होने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है के शोभायात्रा का ग्राम सेमरीहरचंद में भव्य स्वागत किया जाएगा।

भोपाल में 4 मई को होगी लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की बैठक

बैतूल। भोपाल में मप्र लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय महासमिति की बैठक 4 मई रविवार को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के बैतूल जिलाध्यक्ष कमलेश चौहान ने बताया कि यह बैठक प्रदेश के सभी 55 जिलों के संघ पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कमलेश चौहान ने बताया कि हाल ही में मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर केन्द्र के समान 55 प्रतिशत करने, एरियर की राशि का भुगतान किये जाने तथा वर्ष 2016 से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

आकर्षक वेदियों पर 740 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, परिजनों को उठाना पड़ी परेशानी

पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुआ विवाह समारोह, जनप्रतिनिधियों ने दिया आशीर्वाद

संजय द्विवेदी, बैतूल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में 740 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सभी वर-वधु ने मंत्रोच्चार के बीच खुशी-खुशी एक दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। सभी ने आकर्षक वेदियों में 7 फेरे लिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गाजे-बाजे के साथ बारात निकली, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, विधायक हेमंत खंडेलवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नपाध्यक्ष बैतूल पार्वतीबाई बारस्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव सहित समस्त पार्षदगण और जनपद सदस्य शामिल हुए। प्रशासन द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन की समुचित व्यवस्थाएं तो सुनिश्चित की गई थी, परंतु गर्मी अधिक होने के चलते विवाह स्थल पर वर-वधु रुमाल और गमचे से ही हवा लेते देखे गए, कुल मिलाकर विवाह स्थल पर पंखे-कूलर और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से वर-वधु के परिजनों को खासी परेशानी उठाना पड़ी।

गरीब परिवार की बेटियों की चिंता कर भव्यता और गरिमा के साथ कराया जा रहा विवाह : केन्द्रीय राज्य मंत्री - मंचीय कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल प्रेरक नेतृत्व में मध्यप्रदेश स्वर्णिम राज्य बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली, संपन्नता और ऐश्वर्य लाने के लिए विविध प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। पात्र परिवारों को निशुल्क राशन, पीएम आवास, गति देने वाली सड़कों का जाल, उज्जवला गैस कनेक्शन, 5 लाख तक का निशुल्क उपचार,लाडली बहना योजना के तहत प्रतिमाह राशि, घरों में शौचालय, सुचारू बिजली, एवं नल से जल पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की चिंता कर पूरी भव्यता और गरिमा के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें पुरुष और प्रकृति एक होकर एकाकार हो जाते है और नव जीवन में प्रवेश कर गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाते हैं और उत्कृष्ट संततियों को जन्म देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से सभी नव युगल दंपतियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।

निर्धन परिवारों का विवाह कराकर आर्थिक संबल प्रदान कर रही प्रदेश सरकार : विधायक हेमंत खंडेलवाल- विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सभी नव दंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज प्रशासन द्वारा सभी 740 जोड़ों का बेहतर व्यवस्थाओं के साथ विवाह सम्पन्न कराया गया हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत निर्धन परिवारों का विवाह करा मध्यप्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। विवाह जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को सभी परंपराओं के साथ धूमधाम से कर नव दंपतियों को 49 हजार की राशि भी प्रदान की जा रहीं है। इस आयोजन में सभी जनप्रतिनिधि आज एक जगह एकत्रित होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि उनका आने वाला जीवन सुखमय हो। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धुर्वे ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रहीं हैं। नपाध्यक्ष श्रीमती बारस्कर ने कहा कि गरीब परिवार बेटियों की विवाह अच्छे से करानी की चिंता प्रदेश सरकार ने की हैं। 4 करोड़ 15 लाख की राशि से बैतूल में सभी 740 जोड़ो का विवाह धूमधाम से किया जा रह रहा हैं। सभी अतिथियों ने प्रत्येक वेदियों में जाकर नव युगल दंपतियों से भेंट कर आशीर्वाद दिया।

740 जोड़े में 526 जोड़ों के भगत-भूमकाओं ने कराया विवाह

आदिवासियों संगठन द्वारा पूर्व में ही जिला प्रशासन से मांग की गई थी कि आदिवासी जोड़ों का विवाह परंपरागत एवं रीति रिवाजों के अनुसार भगत- भूमकाओं से कराए जाएं। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने भगत भूमकाओं की भी विवाह स्थल पर व्यवस्था कर रखी थी। भगत भूमकाओं द्वारा 526 आदिवासी जोड़ों का विवाह आदिवासियों के परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। इसके अलावा सामान्य के 11, ओबीसी के 151 सहित कुल 740 जोड़े, जिनमें 526 का जनजातीय रीति रिवाज से, 209 वैदिक पद्धति से एवं 5 का निकाह संपन्न कराया गया। जोड़ों को 49 हजार रुपए की राशि का चेक भी वितरित किए गए।

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमी जोड़े ने भी लिए सात फेरे

जानकारी के मुताबिक सामूहिक विवाह समारोह में एक प्रेमी जोड़े ने सात फेरे लिए है। कई दिनों से यह प्रेमी जोड़ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और युवती गर्भवती भी हो गई। इस प्रेमी जोड़े ने सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर विवाह किया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों बालिग है और शासन के नियमानुसार ही इस जोड़ें को विवाह समारोह में शामिल किया गया। विवाह समारोह के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन का पालन किया गया है शासन के निर्देश है कि दूसरी बार विवाह करने वालों को इस समारोह में विवाह करने के लिए पात्रता में नहीं रखा है। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें गर्भवती युवती ने विवाह समारोह में शामिल होकर सात फेरे लिए है।

ट्रैफिक प्लान के तहत बंद रहे भारी वाहनों

इस समारोह को देखते हुए प्रशासन ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की थी। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक भारी वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों सहित भारी वाहनों का शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित मार्गों में गेंदाचौक से हमलापुर चौक, फॉरेस्ट बैरियर से माचना ब्रिज, चक्की रोड से कॉलेज चौक और गंज मस्जिद से कॉलेज चौक तक के क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा अतिथियों के वाहनों के लिए तीन पार्किंग स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, उत्कृष्ट विद्यालय (मुल्ला पेट्रोल पंप के पास) और सतपुड़ा क्लब परिसर (रेन बसेरा चौक) निर्धारित किए गए थे। इसके साथ ही अंबेडकर चौक पर भीड़ बढ़ने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने कुल 12 सेक्टर बनाए गए थे। विवाह संपन्न करने के लिए 190 से अधिक वेदियां बनाई गई, जिसमें समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जनपद और महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला तैनात रहा।

विभागीय भर्ती और उपकरण खरीदी समय से करें पूर्णः उप मुख्यमंत्री शुक्ल

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई के दिए निर्देश

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लम्बित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संविदा कर्मियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही, उन्होंने विभागीय रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधोसंरचना विकास के कार्यों की और निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों। साथ ही, स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीदी की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकें। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैतूल जिला योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रदेश में अग्रणी

सीएम डैशबोर्ड में हासिल किया पहला स्थान

बैतूल। प्रदेश में संचालित शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैतूल जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर बैतूल को 38 विभागों की

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाधिक हैं। जिला कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की सतत निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली के परिणाम स्वरूप यह उपलब्धि हासिल की हैं। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की सतर्क निगरानी ने यह सुनिश्चित किया कि लाभकारी योजनाएं समय पर और पारदर्शिता के साथ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे।

मुलताई-बैतूल हाईवे पर दो बसों में टक्कर, 10 यात्री घायल

बैतूल/मुलताई। मुलताई के एनस गांव के पास शुक्रवार दोपहर 2 बजे दो बसों में टक्कर हो गई। हादसे में 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को मुलताई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर से रायपुर जा रही एमआर ट्रैवल्स की बस और बैतूल से छिंदवाड़ा जा रही फिरोज खान ट्रैवल्स की बस में टक्कर हो गई। एमआर बस ने तेज रफ्तार में फिरोज खान बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद फिरोज खान की बस सड़क से 20 फीट दूर खेत में पहुंच गई। इस हादसे के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत डायल 100 और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायल यात्रियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि, किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है। हादसे में धनराज गुर्जर निवासी राजस्थान, चंदा बाई निवासी जयपुर, दुर्गादास ओझा निवासी जोधपुर, प्रमिला पाटणकर निवासी बाबरबोह मुलताई, जितेंद्र पिता श्री चंद्र पवार निवासी छिंदवाड़ा खान बस चालक, लता पवार निवासी दुनावा, मनीषा सिरसाम नगरकोट, रिया परिहार दुनावा, बलिराम पाटनकर निवासी बाबरबो, जीविका पिता गुलसु निवासी पाठखेड़ा के घायल होने की सूचना मिली है।

सारणी हाईवे पर फिर दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत

बैतूल। जिले के सारणी शहर में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से हडक़ंप मच गया है। दरअसल शहर से होकर गुजरने वाले स्टेट हाइवे पर यह देखा गया हैं। इस बार रिहायशी क्षेत्र के नजदीक तेंदुआ दिखाई दिया है, इसे पहले भी यहां बाघ दिखाई दिया था। इस बार तेंदुए नगर शुरू होने से पहले सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की बाउंड्री वॉल के पास दिखाई दिया है। राजेश गुगनानी ने बताया कि मै सारणी अपने व्यापारी मित्र के बेटे आकाश साहू की शादी में आया था। लगभग रात्रि 12.30 से 1 बजे के बीच में जब अपने घर बैतूल लौट रहा था। तभी मेरी गाड़ी के सामने तेंदुआ आ गया और तेंदुआ काफी देर तक हाईवे पर घूम रहा था। मैंने शादी में आए लोगों को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया कि वह अभी बाइक से वहां से नहीं निकले, प्लांट के बाउंड्री वॉल के पास तेंदुआ घूम रहा है। सूत्रों के अनुसार पावर प्लांट की बाउंड्रीवाल होने की वजह से वह उसे पार करने में सफल नहीं हो पा रहा। बार-बार

तेंदुआ बाउंड्रीवाल की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। लेकिन बाउंड्रीवाल ऊंची होने की वजह से उसे पार नहीं कर पा रहा था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेंदुआ राख बांध वाले क्षेत्र से आया होगा और एबी-टाइप कालोनी की तरह जा रहा होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में भरपूर पानी और बड़ी-बड़ी हरी घास हैं। चुकी यहां जानवर रहते हैं इसलिए शेर और तेंदुए का यह मनपसंद इलाका है।

शेर और तेंदुआ का पसंदीदा क्षेत्र है सारणी- सारणी इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी मनपसंद क्षेत्र हो गया है। आए दिन यहां जंगली जानवर देखे जा रहे हैं। जिस तेजी से जंगली जानवरों की मौजूदगी सारनी और इसके आसपास के क्षेत्रों में मिल रही है। उससे यह कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि बाघ और तेंदुए समेत अन्य जंगली जानवरों का पसंदीदा क्षेत्र सारणी और उसके आसपास का क्षेत्र है। गौरतलब है कि साल 2018 के बाद से अब तक कई बार बाघ, तेंदुए, भालू समेत कई जंगली जानवरों की मौजूदगी रिहायशी क्षेत्र में बनी है। जंगली जानवरों और इंसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन समय में वन विभाग द्वारा कई चिन्हित स्थानों पर टीम भी तैनात की थी। एक बार फिर हाईवे पर तेंदुए की मौजूदगी ने वन विभाग का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

राइट क्लिक

जनगणना: मोदी सरकार ने मंडल 3.0 का रिमोट विपक्ष से छीन लिया है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

केन्द्र मोदी सरकार द्वारा विपक्ष के दबाव के चलते इस साल देश में जाति गणना कराने के फैसले के साथ ही मंडल राजनीति 3.0 का आगाज भी हो गया है। मंडल 3.0 इसलिए क्योंकि इस फैसले के साथ हमे नए अंतर्संघर्षों के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। दूसरे, पहलगाम हमले में 'कल्पना से भी कड़ी सजा' के दावे के बीच अचानक इस 'कास्ट स्ट्राइक' को लेकर भी देश में भारी हैरानी है। उधर जाति जनगणना को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ मची है, वहीं सियासी हल्कों में यक्ष प्रश्न यह है कि इस 'ऐतिहासिक निर्णय' का अंतिम राजनीतिक लाभांश किसके खाते में जाएगा? भाजपानीत एनडीए के या फिर कांग्रेसनीत इंडिया गठबंधन के? फायदा अगर दोनो को मिलेगा तो ज्यादा किसे मिलेगा? अलबत्ता इस जातिवादी सियासत का असली धमाका तो तब होगा, जब जाति की जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक व सरकारी नौकरी, शिक्षा में अधिकाधिक आरक्षण की मांग को लेकर जातियों के भीतर तनाव और अंतर्संघर्ष बढ़ेगा, देश में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने का दबाव बनेगा। ओबीसी जातियों की संख्या व आबादी के खुलासे के बाद ठंडे बस्ते में पड़ी जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने का दबाव भी मोदी सरकार पर बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर भी तलाशा जाएगा कि जाति गणना कराने से भाजपा और संघ की हिंदू एकीकरण की मुहिम को गहरी चोट पहुंचेगी या फिर यह अभियान जातीय अस्मिता के आवरण में और मजबूत होगा? वैसे जाति जनगणना के फैसले से सर्वाधिक आक्रोश अगड़ी जातियों में है।

देश में मंडल कमंडल राजनीति के उभार के साथ ही जाति का मुद्दा सियासत के केन्द्र में रहा है। पहले यह जातियों के वर्ग तक सीमित था, अब यह जातियों की संख्या और जनसंख्या की गिनती तक पहुंच गया है। इसे ही सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जा रही है। आजादी के बाद देश में हुई हर जनगणना में अजा/जजा वर्ग की आबादी की गणना तो होती रही है, लेकिन सभी जातियों के आधार पर जनसंख्या जन गणना से सरकारें बचती रही हैं। तर्क था कि इससे देश निचले स्तर विभाजित होगा। यहां तक कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्ववाली यूपीए-2 सरकार ने भी 2011 की जनगणना में जातियों की सामाजिक-आर्थिक गणना कराई, लेकिन उसका डाटा जारी नहीं किया। बताया जाता है कि इस जनगणना में देश में 46 लाख जातियां सामने आईं, जिसे देख सरकार के होश उड़ गए। बाद में मोदी सरकार ने भी ये आंकड़े उजागर न करने में ही भलाई समझी। जाति जनगणना की मांग जोरशोर से उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यह मांग कभी नहीं की कि उनकी सरकार के दौरान हुई जातियों की आर्थिक-सामाजिक गणना के आंकड़े मोदी सरकार तो जारी करे। हालांकि अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा जनगणना के साथ ही जातिगणना कराने के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि सरकार हमारे दबाव में ही यह फैसला लेने पर विवश हुई है, लेकिन सरकार इसके आंकड़े जारी करने की टाइमलाइन भी स्पष्ट करे।

जहां तक इस मांग को लेकर हिंदू एकता की बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक की बात है तो उसने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजो के बाद केरल के पलक्कड में आयोजित बैठक में जातिगणना को हरी झंडी दे दी थी। संघ ने अपने आंतरिक मंथन में यह बूझ लिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से 32 कम मिलने के पीछे प्रमुख कारण यूपी, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में कांग्रेस, सपा, राजद आदि दलों द्वारा जातिगणना कराने की मांग को मोदी सरकार द्वारा टालते जाना है। क्योंकि जाति जनगणना सीधे तौर पर आरक्षण की आकांक्षा से जुड़ी है। ओबीसी वर्ग में यह बेचैनी लगातार बढ़ रही थी कि उनकी जातियों की सही संख्या व जनसंख्या का प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने से उसे अपेक्षित सामाजिक- राजनीतिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ कल तक भाजपा और संघ का मानना था कि जातिवाद, हिंदू एकता के गुब्बारे के लिए सुई के समान है। क्योंकि जातियों में बंटते ही हिंदू गौरव, संकीर्ण जातिबोध में सिमट जाता है, जिससे सकल हिंदू एकता तार तार होने लगती है। लेकिन लगता है कि यह सोच अब यू टर्न ले चुकी है। फोकस अब इस बात पर है कि चूंकि जाति हिंदू समाज की एक अनिवार्य बुराई है, लिहाजा इसके सकारात्मक राजनीतिक दोहन के बारे में ज्यादा सोचा जाना चाहिए।

ऐसे में यह तय था कि कल तक जाति जनगणना के खिलाफ रही भाजपा इसके पक्ष में न सिर्फ फैसला लेगी बल्कि इसे आजादी के बाद देश में पहली बार कराने का श्रेय भी लेगी। ऐसे में संभव है कि योगी आदित्यनाथ अब नया नारा 'बंटेंगे तो जुटेंगे' भी दे दें।

कहा यह भी जा रहा है कि इसका फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन चूंकि इस बार जनगणना डिजीटली होनी है, इसलिए जातिगणना की प्रक्रिया, पैमाने और तकनीकी प्रावधान करने में वक्त लगा। बीते तीन दशकों में देश में जहां जातिवादी राजनीति के उभार ने यूपी-बिहार जैसे राज्यों में बरसों सत्ता में रही कांग्रेस के जनाधार को जातिवादी राजनीति करने वाले दलो की तरफ मोड़ दिया तो वहीं बाद में भाजपा और संघ ने ओबीसी के बड़े वर्ग को नए सिरे संगठित कर हिंदुत्व की पताका उसके हाथ में थमा दी। इसी का नतीजा है कि बीते एक दशक से देश की कमान नरेन्द्र मोदी के रूप में एक ओबीसी के नेता के हाथों में हैं।

यहां गौरतलब है कि वर्तमान में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण 1931 की जाति जनगणना के आंकड़ो के आधार पर ही दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से जातिगणना हुई ही नहीं। उस के हिसाब से देश में सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की 46 (मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी के अलावा), ओबीसी की 2633, अजा वर्ग की 1270 व अजजा की 748 जातियां हैं। अब विस्तृत जाति जनगणना के बाद यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है।

अगर ओबीसी की बात करें तो मोदी सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग में आरक्षण के न्यायसंगत वितरण के लिए गठित जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ओबीसी में जहां 10 जातियों ने आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठाया, वहीं 983 जातियों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए आयोग ने लाभान्वितता के आधार पर ओबीसी जातियों को चार उप श्रेणियों में बांटकर उनके आरक्षण की सीमा तय करने की सिफारिश की थी। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास है। इस बीच बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में सरकारों ने जाति सर्वे कराया है। लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर सवाल है। चूंकि ओबीसी वर्ग में सर्वाधिक जातियां होंगी, इसलिए जाति जनगणना से इस वर्ग में जातियों का माइक्रो विभाजन बहुत ज्यादा हो सकता है। उस स्थिति में आरक्षण से वंचितों को उसका लाभ मिलने या ऐसी मांग करने वाली जातियों का नए सिरे ध्रुवीकरण होगा, लेकिन उसका वास्तविक सियासी लाभ वो पार्टियां ही प्रभावी ढंग से उठा पाएंगी, जिनके पास इस मुद्दे को वोटों में भुनाने के लिए सक्षम संगठन और राजनीतिक तंत्र हो। ऐसा मजबूत तंत्र फिलहाल भाजपा के पास ही दिखाई देता है। जाति जनगणना के बाद देश में राजनीतिक आरक्षण भी लागू होगा, जिसमें विधानमंडलों में सर्वाधिक सीटें ओबीसी के लिए ही आरक्षित करनी होंगी। साथ ही सभी जाति वर्गों में महिला आरक्षण की संख्या भी तय होगी। हालांकि संख्या को ही आधार मानने पर योग्यता, गुणवत्ता और प्रतिभा के पैमाने हाशिए पर जा सकते हैं। जिसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि जातीय विभाजक रेखाओं के बावजूद काबिलियत की अहमियत और जरूरत कायम रहेगी।

बहरहाल मोदी सरकार का जाति जनगणना कराने का यह फैसला 'राजनीतिक डेमेज कंट्रोल' के साथ-साथ भविष्य की संकीर्ण जातिवादी राजनीति की नई रेखाएं खींचने का आगाज भी है। दक्षिणी राज्यों की राजनीति पर भी इसका असर दिख सकता है। देश में जातियों की संख्या और उसकी जनसंख्या के आंकड़े उजागर होने के बाद आरक्षण की नई छीना-झपटी शुरू होगी। इसमें कौन शेर साबित होगा, अभी कहना मुश्किल है। सवाल यह भी है कि क्या जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठाते रहने का असल फायदा कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों को होगा या फिर इस मांग को अमलीजामा पहनाने और उसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली भाजपा को होगा, यह सस्पेंस दिलचस्प है। बेशक कांग्रेस व जातिवादी राजनीति करने वाले अन्य दल इस फैसले का श्रेय लेने का पूरा प्रयास करेंगे, और वो जायज भी है, लेकिन इसका लंबे समय तक सियासी फायदा उठा सकने वाले प्रभावी मैकेनिज्म और इको सिस्टम इन दलों के पास नहीं है। जातिवार जनसंख्या सामने आने के बाद जातिवादी दल अपने अंतर्विरोधों का शिकार भी हो सकते हैं। 'एक राष्ट्र' और 'हिंदू एकता' की बात करने वाली भाजपा इसमें अपनी प्रासंगिकता कैसे कायम रख पाती है, यह देखने की बात है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा बिहार में छः माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। जातिगणना के साथ भाजपा ये आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण करने और उसे जारी करने का क्रेडिट हर कदम पर लेने की भरपूर कोशिश करेगी। फिलहाल मोदी सरकार विपक्ष की मांग के आगे हथियार डालती भले नजर आए, लेकिन जाति जनगणना की मांग मानकर उसने विपक्ष के हाथों से इस मुद्दे का रिमोट कंट्रोल बड़ी चतुराई से छीन लिया है। हालांकि जाति जनगणना हो भी जाए तो उसके आंकड़े कब और किस राजनीतिक दांव के तहत उजागर होंगे, कोई नहीं जानता।

॥ मंदिरम् ॥ 99

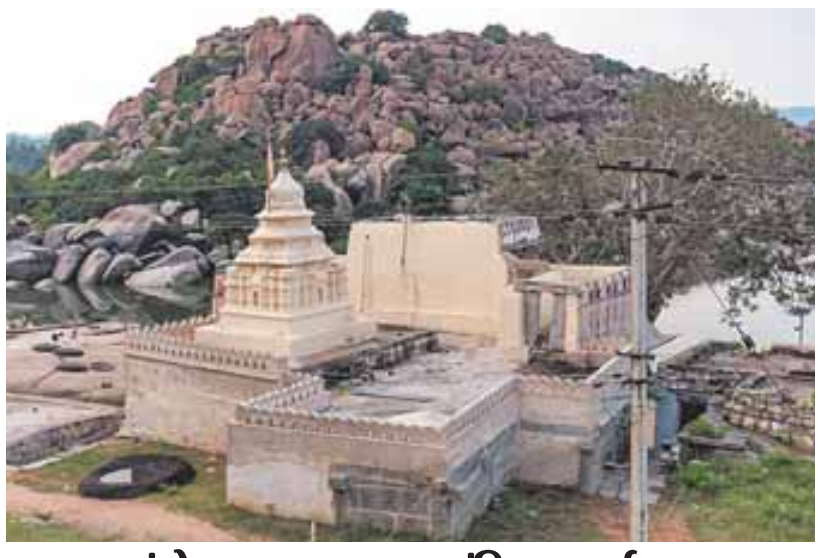

यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर, कर्नाटक

यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर, भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ राम और हनुमान की पहली मुलाकात हुई थी। यह मंदिर हम्पी में अंजनेया पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर प्राचीन किष्किंधा नगरी में स्थित है, जहाँ वानर राज्य सुग्रीव का शासन था। यह मंदिर रामायण काल में श्री राम और हनुमान के पहले मिलन के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्री व्यासराज द्वारा स्थापित किया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु थे। इसे प्राणदेव मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर गुफा के अंदर स्थित है और 570 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है। मूर्ति को ग्रेनाइट की चट्टान पर दर्शाया गया है। हनुमान को शतकोना यंत्र (छह कोनों वाला यंत्र) के केंद्र में पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है जिसे यंत्र के नाम से जाना जाता है। उनका दाहिना हाथ व्याख्यानमुद्रा में है और बायां हाथ ज्ञानमुद्रा में है। वे शरीर पर किरीटमुकुट और अन्य सामान्य आभूषण पहनते हैं। यंत्र के ऊपर 12 बंदरों की नक्काशी है जो एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए हैं और उनका मुख पीछे की ओर है। यह श्री व्यासराज द्वारा भगवान के आशीर्वाद से पहले की गई 12 दिनों की प्रार्थना का प्रतिनिधित्व है।

बेकाबू होकर पलटी पिकअप, 4 की मौत

विदिशा के सिरोंज से बारात लौट रही थी, सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

विदिशा (नप्र)। विदिशा के लटेरी में बारातियों से भरा पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया। इसमें दूल्हे के बहनोई, कजिन भाई-बहन समेत चार की मौत हो गई। बारात सिरोंज से इंदौर लौट रही थी। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर हैं। हादसा गुरुवार रात 10 बजे मदागन घाटी में हुआ। सूचना मिलते ही लटेरी एसडीओपी अजय मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बारात इंदौर के आउलीखेड़ा गांव लौट रही थी।पिकअप में 16 लोग सवार थे, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। सभी लोग पत्थर के सिलबट्टे बनाने का काम करते हैं।

दूल्हा-दुल्हन दूसरी गाड़ी में थे सवार- हादसे के बाद घायलों को तत्काल लटेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। दूल्हा-दुल्हन दूसरी गाड़ी में सवार थे। देर रात कलेक्टर अंशुल गुप्ता और एसपी रोहित काशवानी लटेरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों से बातचीत की।

दूल्हे के बहनोई, कजिन भाई-बहन की मौत- रिश्तेदार संगीता ने बताया कि रवि टाकिया

की शादी थी। बुधवार को बारात में करीब 35 लोग दो पिकअप और एक इंडिका से सिरोंज आए थे। गुरुवार को शादी के बाद रात 9 बजे बारात वापस जाने के लिए निकली थी। कुछ ही देर बाद एक्सीडेंट हो गया। इसमें दूल्हे रवि के बहनोई, बड़े पापा के बेटे-बेटी और मामा के एक बेटे की मौत हो गई।

दूल्हे ने कहा- दो पिकअप से लौट रहे थे रिश्तेदार- दूल्हे रवि टाकिया ने बताया कि हम दो भाई और सात बहनें हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूं। हम प्लास्टिक का सामान बेचने का काम करते हैं। बुधवार दोपहर बारात लेकर निकले थे। माता-पिता घर पर रुके थे। गुरुवार को फेरे हुए। शाम को खाना खाने के बाद 9 बजे करीब बारात विदा हुई। मैं और दुल्हन इंडिका कार में थे। दो पिकअप में उनके रिश्तेदार थे। मेरी गाड़ी आगे थी। बीच में जो पिकअप चल रही थी, वह पलट गई। पीछे दूसरी पिकअप आ रही थी। उन्होंने पिकअप को पलटी देखा तो वह वही रुक गई थी। हम लोग वापस लौटे। रिश्तेदारों ने हमारी गाड़ी को घर के लिए रवाना कर दिया।

ड्राइवर ने कहा- परिवार के चार की गई जान

ड्राइवर तूफान सिंह ने बताया कि हम लोग शादी के बाद अपने घर इंदौर जा रहे थे। रास्ते में घाटी से पहले गाड़ी पलट गई। गाड़ी में करीब 16 लोग सवार थे। मेरा भाई, बहन, मामा का लड़का और साला शांत हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर गाड़ी कैसे पलट गई।

नायब तहसीलदार इदरीश खान ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों को विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया था। यहां इलाज के दौरान एक और की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। उसे भी रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का यहीं इलाज चल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बस दुर्घटना में 4 यात्रियों के आकस्मिक निधन पर जताया शोक, 2-2 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा जिले के लटेरी तहसील में बस दुर्घटना में 4 यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस इन्दौर से सिरोंज जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोकाकुल परिजन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

जबलपुर समेत 22 जिलों में बारिश, 10 जिलों में आंधी

5 जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट ; अगले चार दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) के एक्टिव होने से ओले-बारिश का दौर जारी है। पिछले 6 दिन से प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम बदला हुआ है। कहीं तेज आंधी-बारिश हो रही है तो कहीं ओले भी गिर रहे हैं।

पिछले 24 घंटे में जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत 22 जिलों में पानी गिरा। 10 जिलों में आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिले-छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिर सकते हैं। प्रदेश में अगले चार दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

भिंड में शुक्रवार सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश का दौर सुबह करीब 6:30 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते शहर की बिजली बंद हुई। हालांकि, सुबह के समय होने वाली बारिश से तापमान भी कम हुआ है। इसके साथ ही मुरैना में भी तेज बारिश हुई। ग्वालियर में भी हल्की बरसात हुई।

जबलपुर में 65 किमी की रफ्तार से चली हवा- जबलपुर में हवा की रफ्तार 65 किमी, शहडोल में 63 किमी,भिंड में 56 किमी, सिंगरौली में 50 किमी, मंडला में 47 किमी, सिवनी में 45किमी,आगर-मालवा में 39 किमी, शाजापुर में 36 किमी,नीमच में 30 किमी और अनूपपुर में 26 किमी प्रतिघंटा रही। भिंड में सुबह से गरज-चमक के साथ बारिश हुई।

आज इन जिलों में आंधी चलने का अलर्ट

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर में हवा की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रतिघंटा तक रह सकती है। वहीं, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज-चमक और हल्की बारिश होने के आसार है।

5 मई तक बारिश का दौर रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार, 5 मई तक प्रदेश में बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ जिलों में दिन में गर्मी रहेगी, जबकि शाम के बाद मौसम बदलेगा।

डॉ. अरुणा कुमार की नियुक्ति पर विवाद

जूडा-एमटीए का अल्टीमेटम

भोपाल (नप्र)। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. अरुणा कुमार को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) बनाए जाने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को पदभार ग्रहण करते ही जहां एक ओर उन्होंने विभागीय बैठकों का दौर शुरू किया, वहीं दूसरी ओर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जूडा) और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए) ने इस नियुक्ति का विरोध करते हुए सरकार को 24 घंटे में आदेश निरस्त करने की चेतावनी दी है। दोनों संगठनों ने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

जूडा ने जताया विरोध, एमटीए से मांगा समर्थन- डॉ. कुमार की नियुक्ति के विरोध में सबसे पहले जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जूडा) सामने आया। गुरुवार को ही एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को पत्र भेजकर इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। जूडा ने आरोप लगाया कि डॉ. कुमार का प्रशासनिक व्यवहार पूर्व में विवादास्पद रहा है, जिससे कॉलेजों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ है। जूडा ने मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए) को पत्र लिखकर समर्थन भी मांगा। उन्होंने पत्र में लिखा कि डॉ. कुमार के कार्यकाल में एक महिला जूनियर डॉक्टर ने मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या का कदम उठाया था।

म.प्र.सरकार को केंद्र से मिलेंगे 44255 करोड़ रुपए

ग्रामीण विकास, पीएचई, महिला बाल विकास के फंड में इजाफा, खाली रहेगी चार विभागों की झोली

भोपाल (नप्र)। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए मध्यप्रदेश को दी जाने वाली राशि के प्रावधानों की घोषणा कर दी है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र ने मोहन यादव सरकार को करीब आठ हजार करोड़ रुपए अधिक देने का फैसला किया है। एमपी सरकार को अगले वर्ष 31 मार्च तक इसका भुगतान किया जाएगा।

वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में एमपी की मोहन सरकार को 37652 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। लेकिन तब 16155 करोड़ रुपए कम मिले थे और एमपी के हिस्से में 21497 करोड़ रुपए ही आए थे। अब चालू वित्त वर्ष में पिछले बजट से अधिक राशि की घोषणा के बाद एमपी में विकास कार्यों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

केंद्र और राज्य का संयुक्त बजट 68519 करोड़ का- प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन के लिए कुल

68519.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का फैसला किया गया है। इसमें 44255.33 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी जबकि 24263.71 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंश के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार कई अन्य योजनाओं में राशि अलग से भी जारी कर सकती है जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

केंद्र ने एक माह में दिए 283 करोड़ रुपए

केंद्र और राज्य के समानुपात के आधार पर योजनाओं के खर्च के लिए चालू वित्त वर्ष में मोदी सरकार ने मोहन सरकार को 28 अप्रैल तक की स्थिति में 283.46 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं। इसमें लोक निर्माण विभाग को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 27.24 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 39.14 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र ने वित्त विभाग को 217.07 करोड़ रुपए एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर एक्सटर्नली एडेड खर्च के लिए दिए हैं।

चार विभागों को केंद्र से शून्य राशि, चिकित्सा शिक्षा का अलग बजट नहीं

4 विभाग ऐसे हैं जिनके लिए शून्य बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसे विभागों में पर्यटन, संस्कृति, वित्त और भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग शामिल हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस साल कोई बजट नहीं मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को मर्ज करने का फैसला लिया था। लेकिन इसकी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू होने के बाद पूरी हो पाई थी। इस कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र से राशि चिकित्सा शिक्षा विभाग के मद में दी जा रही थी।

कृषि की ताकत, उद्योग का सहारा
बढ़ेगा किसान, बढ़ेगा देश हमारा

कृषि-उद्योग समागम 2025

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

शुभारंभ

मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव
द्वारा

3 मई, 2025 | दोपहर 12:00 बजे
कृषि उपज मंडी ग्राउंड
सीतामऊ, मंदसौर

कृषि उद्योग समागम - किसानों के हित में नई पहल

तकनीक को प्रोत्साहन
किसान भाई-बहन एक ही मंच पर कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन के, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त आधुनिक यंत्रों एवं नवीनतम तकनीकों से परिचित होंगे

आधुनिक आदान को बढ़ावा
सिंचाई संयंत्र, बीजों की उन्नत एवं नवीनतम किस्मों तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित फर्टिलाइजर्स की जानकारी से भी अवगत होंगे

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को नए आयाम
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की नवीनतम पद्धतियों, डेयरी टेक्नोलॉजी तथा मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों की सटीक जानकारी एवं मार्गदर्शन

कृषि और उद्योग की साझेदारी
कृषि एवं उद्यानिकी फसल आधारित उद्योगों से जुड़े उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्रेता-विक्रेता, निर्यातक एवं किसान संगोष्ठी के माध्यम से तलाशेंगे साझेदारी के अवसर

किसान हित की योजनाओं में पंजीयन
फसल बीमा कंपनी, किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंकर्स द्वारा किसानों के साथ जानकारी साझा की जाएगी तथा किसान हित की योजनाओं में होगा किसानों का पंजीयन

D-11021/25 सीधा प्रसारण webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @JansamparkMP JansamparkMP #कृषि_उद्योग_समागम_MP

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी
आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2025